ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4

कही नरक की घाटी ना बन जाए? पतरातू घाटी

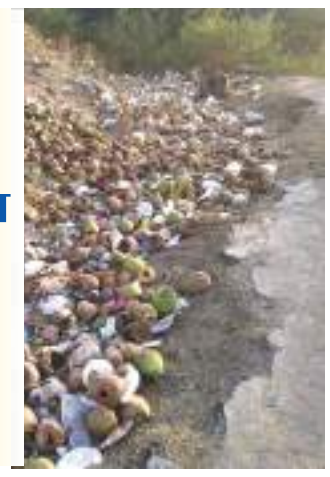

रविवारीय, 14- 20 फरवरी 2021 वर्ष- दो, अंक-28, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः 5 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

बीएयू वैज्ञानिकों के दल ने उलीहातू व कुददा का दौरा किया

रांची : कुलपति डॉ ओंकार नाथ सिंह के निर्देश पर बीएयू वैज्ञानिकों के दल ने खूँटी जिले में स्थित उलीहातू व कुददा गाँव का दौरा किया. दल ने दोनों गाँवों में समन्वित कृषि प्रणाली एवं इको टूरिज्म की संभावना तथा ग्रामीण परिवेश में कृषि प्रणाली की स्थिति का आकलन किया. परियोजना के अन्वेंशक डॉ एमएस मल्लिक ने जानकारी दी कि विश्व बैंक संपोषित राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना (नाहेप) के तहत दोनों गाँवों में समन्वित कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न फसलों की वैज्ञानिक खेती से लेकर पशु पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, मछली पालन, कृषि यंत्र उपादानों को दिया जायेगा. यह कार्यक्रम ग्रामीणों के रोजगार सृजन एवं आय में बढ़ोतरी के उद्देश्य से चलाया जायेगा। दल ने दोनों गाँवों में परंपरागत कृषि के स्थान पर लाभकारी कृषि तकनीकी को बढ़ावा की आवश्यकता जताई।

पर्यावरण नियमों के उल्लघंन की होड़

वरीय संवाददाता

उत्तराखंड में आये एवलांच के दुखद हादसे में दर्जनों लोगों की मौत हो गयी और सैकड़ो लापता हैं। कीचड़ और मलबे से भरे सुरंग को अथक प्रयास से खोदने के बाद भी वहां से जीवित मजदूरों के बजाय उनके शव निकल रहे हैं। यह सब देशवासियों को बहुत आहत करता है। लेकिन इन सबके पीछे सरकारों की भी भी भयंकर लापरवाही रही है। जानकार यह बताते हैं कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों से लेकर अन्य राज्यों में भी उन नियमों और चेतावनियों की अनदेखी होती रही है जो बाद में कभी विकराल रूप धारण कर किसी आपदा का कारण बन सकता है। पूरे देश में तकरीबन सभी राज्यों में पर्यावरण नियमों की अनदेखी होती है। यह अनदेखी किसी प्राकृतिक आपदा से लेकर अन्य नुकसानों का कारण बनते हैं।

एक आंकड़े के अनुसार पिछले पांच वर्षों में 1798 परियोजनाओं में किया गया पर्यावरण मंजूरी की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। इनमें सबसे ज्यादा परियोजनाएं हरियाणा से सम्बन्ध रखती हैं जहां 259 परियोजनाओं में पर्यावरण मंजूरी सम्बन्धी शर्तों की अवहेलना की गई है ।पिछले पांच वर्षों में करीब 1798 परियोजनाओं ने देश में पर्यावरण मंजूरी सम्बन्धी शर्तों का उल्लंघन किया है यह जानकारी राज्यसभा में श्रीमती वेदना चौहाण द्वारा पूछे एक प्रश्न के जवाब में सामने आई। इन परियोजनाओं में सबसे ज्यादा हिस्सा औद्योगिक परियोजनाओं का है जिसमें 679

परियोजनाओं में नियमों का उल्लंघन किया गया है इसके बाद इन्फ्रास्ट्रक्चर और सीआरजेड की 626 परियोजनाएं, कोयले को छोड़कर खनन से जुड़ी 305 परियोजनाएं, कोयला खनन 92 परियोजनाएं, थर्मल पावर से जुड़ी 59 और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की 37 परियोजनाएं शामिल हैं ।गौरतलब है कि देश में ईआईए अधसिूचना में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन (एमओईएफ व सीसी मंत्रालय) द्वारा परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दी जाती है। किसी भी औद्योगिक, इन्फ्रास्ट्रक्चर या खनन परियोजना को शुरू करने से पहले सरकारी या प्राइवेट एजेंसी को पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) की रिपोर्ट सौंपनी होती है। इस रिपोर्ट में परियोजना के कारण पर्यावरण या जंगल को होने वाले संभावित नुकसान और उसकी भरपाई के तरीकों की जानकारी दी जाती है। इसी के आधार पर सरकार की ओर से मंजूरी मिलने के बाद ही परियोजना शुरू करने का प्रावधान है लेकिन इसके बावजूद कई परियोजनों में मंजूरी मिलने के बाद मंजूरी की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है।

झारखंड भी एक पठारी राज्य है और यहां प्राकृतिक संसाधनों की भी प्रचुरता है। लेकिन इसके दोहन से लेकर राज्य के जिलों में सौंदर्यीकरण के नाम पर तथा खनिजों के खनन में भयंकर लापरवाहियां देखने को मिलती हैं। यहां तो सरकार की नाक के नीचे से महज पत्थरों के लिये क्रशर माफियाओं ने एतिहासिक पहाड़ियों तक को खोद दिया है और तालाबों डैमों को बर्बाद कर रहे हैं।

हिमालय से लगते क्षेत्रों में बडे. निर्माण होना आने वाले समय के टाइम बम साबित होंगे। जिन इलाकों में इंसानों को कम आक्सीजन के चलते सांस लेने में दिक्कत होती हैं। वहां बडे. बांध बनाये जा रहे हैं। इस संबंध में वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र और राज्य सरकार को सौंपी हैं। उनकी रिपोर्ट में 2013 में केदारनाथ में आई आपदा का हवाला देते हुए बताया गया है कि जो निर्माण कार्य केदारनाथ में हुये। उसके चलते ही कालांतर में केदारनाथ में बड़ी आपदा आई। उसी तरह नंदादेवी बायो रिजर्व में तो बांध ही बना दिया गया। ये भविष्य के टाइम बम होंगे।

पर्यावरण नियमों की अवहेलना में अव्वल राज्य

यदि राज्य स्तर पर देखें तो इनमें सबसे ज्यादा परियोजनाएं हरियाणा से सम्बन्ध रखती हैं जहां 259 परियोजनाओं में पर्यावरण मंजूरी सम्बन्धी शर्तों की अवहेलना की गई है इसके बाद महाराष्ट्र (221) और फिर उत्तराखंड (194) का नंबर आता है। इसी तरह झारखण्ड में 190, पंजाब में 169, हिमाचल प्रदेश में 152, असम में 109, राजस्थान में 91, उत्तर प्रदेश में 80, तेलंगाना में 72, बिहार में 67 परियोजनाएं, मेघालय में 36 और दिल्ली की 27 परियोजनाएं शामिल हैंवहीं नियमों को ताक पर रखने वालों में कर्नाटक में 25, पश्चिम बंगाल की 19, ओडिशा की 14, छत्तीसगढ़ की 13, चंडीगढ़ की 11 और जम्मू कश्मीर की 9 परियोजनाएं शामिल हैं जबकि त्रिपुरा में 8, आंध्रप्रदेश की 6, केरल की 5, सिक्किम, मणिपुर और मध्यप्रदेश में चार-चार, तमिलनाडु में तीन, गोवा और अरुणाचलप्रदेश में दो-दो और नागालैंड और गुजरात दोनों राज्यों की एक-एक परियोजनाएं शामिल हैं।

रेशम कीट पालन बेहतर आय का माध्यम : रजित रंजन ओखंडियार

रांची : बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि सभागार में शनिवार को सेरीकल्चर एक संभावित एग्रोफोरेस्ट्री मॉडल विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया. टेक्सटाइल मंत्रालय, भारत सरकार अधीन कार्यरत सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बैंगलोर के सदस्य सचिव रजित रंजन ओखंडियार व्याख्यान के मुख्य वक्ता थे. उन्होंने सेरीकल्चर यानि रेशम कीट पालन को कृषि पर आधारित कुटीर उद्योग बताया. कृषि कार्य एवं अन्य घरेलू कार्यों के साथ - साथ इस उद्यम को अपनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत से शीघ्र उत्पादन द्वारा बेहतर आय प्राप्त करने की बात कही है. बताया कि वैश्विक स्तर पर जंगल विकास की निशानी है .भारतीय उपमहाद्वीप का 22 प्रतिशत भूभाग जंगलों से आच्छादित है. अन्य देशों की अपेक्षा उपमहाद्वीप के जंगलो की जैव विविधता बेहतर स्थिति में है. कच्चे रेशम का उत्पादन रेशम कीट पालन से किया जाता है. इसकी प्रमुख गतिविधियों में पौधों की खेती है, जो रेशम के कीट को ग्रहण करती है. कृषि वानिकी प्रणाली में शहतूत, गूलर, पलाश और अर्जुन आदि पौधों को लगाकर सफलता से रेशम कीट का पालन किया जा सकता है .उन्होंने कहा कि पांच किस्मों के रेशम में मलबरी, तसर, ओक तसर, एरि और मुगा सिल्क का उत्पादन करने वाला भारत अकेला देश है. विश्व में चीन के बाद कच्चे सिल्क का भारत दूसरा प्रमुख उत्पादक देश है. जबकि भारत रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता है. देश में चीन से बड़ी मात्रा में मलबरी कच्चे सिल्क और रेशमी वस्त्रों का आयात किया जाता है. वर्ष 2017 में देश में इसका 30 मिलियन टन उत्पादन हुआ था,जो वैश्विक उत्पादन का करीब 16 फीसदी है. तसर सिल्क उत्पादन के मामले में झारखण्ड का देश में अग्रणी स्थान है. प्रदेश में हल्दी, अदरख, अर्जुन, गेहूं एवं धान के साथ, रोड व नहर किनारे पौधों को लगाकर आसानी से रेशम कीट का पालन किया जा सकता है. एक हेक्टेयर क्षेत्र में न्यूनतम 80 पौधों को लगाकर 45 दिनों के बाद तथा वर्ष में 3 से 4 बार कच्चे रेशम को प्राप्त की जा सकती है. इस उद्यम को कृषि वानिकी मॉडल में क्लस्टर में सामुहिक गतिविधियों में शामिल कर एक एकड़ से डेढ़ से दो लाख आमदनी प्राप्त की जा सकती है. उन्होंने इस दिशा में विस्तार गतिविधियों एवं प्रक्षेत्र प्रदर्शन को

बीएयू में सेरीकल्चर एक संभावित एग्रोफोरेस्ट्री मॉडल पर व्याख्यान

.....शेष पेज तीन पर

लग सकता है मानसून का सटीक अनुमान, होगा किसानों को फायदा

एजेंसियां

किसानों को समय से पहले मानसून संबंधी जानकारी प्रदान करने से उन्हें अप्रत्याशित भारी वर्षा या भयंकर सूखे से निपटने में मदद मिल सकती है। भारत में फसलों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए, मानसूनी मौसम में होने वाले बदलाव के शुरुआती पूर्वानुमान के बारे में किसानों को जानकारी दी जानी चाहिए। रीडिंग विश्वविद्यालय और यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम-रेंज वेदर फोरकास्ट (ईसीएमडब्ल्यूएफ) के शोधकर्ताओं ने पहली बार अध्ययन किया कि लंबे समय के लिए दुनिया भर के मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। विशेष रूप से पूर्वानुमान इस बारे में है कि गर्मी में आने वाला मानसून कब शुरू होगा और कितनी बारिश होगी। उन्होंने पाया कि भारत के प्रमुख कृषि क्षेत्रों में मानसून आने के समय से एक महीने पहले ही इसका सटीक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। किसानों को यह जानकारी प्रदान करने से उन्हें अप्रत्याशित भारी वर्षा या भयंकर सूखे की अवधि के लिए पहले से तैयार करने में मदद मिल सकती है, भारत में हमेशा से ही दोनों परिस्थितियां फसलों को नष्ट करने के लिए जानी जाती हैं।

रीडिंग यूनिवर्सिटी के मानसून शोधकर्ता और प्रमुख अध्ययनकर्ता डॉ. अमूल्य चेवुतुरी ने कहा कि

भारतीय मानसून भारत की वार्षिक वर्षा का लगभग 80 फीसदी तक बारिश लाता है, इसलिए कृषि पर इसके आगमन के समय में भी छोटे बदलाव का भारी प्रभाव पड़ सकता है। इन साल-दर-साल होने वाले बदलावों के बारे में सटीक पूर्वानुमान लगाना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यह अनुमान कई परिवारों के लिए सम्पन्नता तथा कईयों के लिए गरीबी का सबब बन सकता है।

अध्ययनकर्ता ने कहा कि भारत के मुख्य कृषि क्षेत्रों में हमने जिस सटीकता से पूर्वानुमान लगाया है, वह प्रणाली लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक अवसर प्रदान करती है। यह पानी की उपलब्धता और किसानों के लिए होने वाले प्रभावों जैसे- सूखे या बाढ़ के बारे में समझने में मदद कर सकता है जिससे खाद्य आपूर्ति को होने वाले खतरे को कम करने का प्रावधान किया जा सकता है ।इस तरह का गहन वैश्विक विश्लेषण केवल तभी संभव है जब सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख शोध संस्थान पूरे धरती के फायदे के लिए एक साथ काम करें। भारतीय मानसून का मौसम हर साल 1 जून से शुरू होता है, जो पूरे उपमहाद्वीप में फैलने से पहले दक्षिण पश्चिम भारत से शुरू होता है।

वैज्ञानिकों ने पहली बार (ईसीएमडब्ल्यूएफ) के नवीनतम मौसमी पूर्वानुमान प्रणाली, एस-ईएएसएस की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए 36 साल के मानसून के आंकड़ों को देखा। इसमें इस बात का अनुमान लगाया गया कि भारतीय मानसून लंबे समय में औसत से कैसे भिन्न होगा। टीम ने 1981-2016 से प्रत्येक वर्ष 1 मई से पूर्वानुमानों की तुलना की जिसके बाद मानसून की वास्तविक अवलोकन का पालन किया गया।

क्लाइमेट डायनामिक्स नामक पत्रिका में प्रकाशित उनके अध्ययन में पाया गया कि बड़े पैमाने पर तापमान और हवाओं जैसे मौसम के बारे में पूर्वानुमान सटीक थे, जिसकी वजह से पूरे भारत में मानसून की वर्षा होती है।

अध्ययन में यह भी पाया गया कि एसईएएसएस गंगा के मैदानों और भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के साथ महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्रों पर जल्दी या देर से मानसून आने की भविष्यवाणी करने में बहुत बेहतर साबित हुआ। इसने उस प्रणाली की कमियों की पहचान की जिससे मॉडल में सुधार किया जा सकता है, संभवतः लंबे समय तक अधिक विस्तृत और सटीक मौसमी मानसून के पूर्वानुमान के बारे में जानकारी दे सकती है। अध्ययन से पता चलता है कि पर्वतीय पश्चिमी घाटों और हिमालयी क्षेत्रों में अधिक वर्षा और देश के उत्तर में गंगा नदी के मैदानी इलाकों और बंगाल की खाड़ी में इसके डेल्टा वाले भाग मैं कम वर्षा हुई। हालांकि, पूर्वानुमान पूरे भारत में मानसून वर्षा पैटर्न के लिए सही थे, जिससे योजना बनाने के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है।

सीसीएल गांधीनगर अस्पताल में निःशुल्क हृदय रोग का चिकित्सीय शिविर का आयोजन

रांची : केन्द्रीय अस्पताल गाँधीनगर के सुपर स्पेशियलिटी क्लीनिक में झारखंड के किसी भी नागरिक का एम्स दिल्ली, मैक्स दिल्ली एवं यशोदा अस्पताल, हैदराबाद के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क जांच एवं चिकित्सीय परामर्श की व्यवस्था सीसीएल द्वारा कराया जाता था। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण यह सुविधा पिछले वर्ष में उपलब्ध नहीं करायी जा सकी जिसे अब लंबे अंतराल के बाद सीएमडी, सीसीएल श्री पी.एम. प्रसाद एवं निदेशकगण के मार्गनिर्देशन में जरूरतमंद लोगों के लिए एक बार पुनः इस सुविधा का शुभारंभ किया गया है। सी.सी.एल. द्वारा सुपर स्पेशियलिटी क्लीनिक केंद्रीय अस्पताल, गांधीनगर मे आगामी 19 फरवरी एवं 20 फरवरी, 2021 को हृदय रोग की जांच एव चिकित्सीय सलाह की व्यवस्था की गई है। यशोदा अस्पताल, हैदराबाद के प्रसिद्ध विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. प्रमोद कुचलाकान्ति (कार्डियोलॉजिस्ट)आगामी19 फरवरी, 2021 को अपराह्न02 बजे से एवं 20 फरवरी, 2021 को सुबह 09 बजे से केंद्रीय अस्पताल, गांधीनगर, कांके रोड, रांची आयेंगे, जहां वे मरीजों की जांच करेंगे तथा चिकित्सीय सलाह देंगे। निःशुल्क हृदय संबंधित चिकित्सीय सलाह का सभी झारखंडवासी लाभ उठा सकते हैं। मरीज के पास यदि पुराने ईलाज की रिर्पोट/जांच के पेपर हों तो उसे अवश्य अपने साथ लाये। यह जानकारी जनसंपर्क विभागाध्यक्ष अनुपम राणा ने दी।

सीएमपीडीआई का भूगर्भ संग्रहालय सभी कार्यदिवस को खुला रहेगा

संवाददाता

रांची सीएमपीडीआई (मुख्यालय), कांके रोड, स्थित भूगर्भ संग्रहालय अब दिनांक 15फरवरी 2021 से (शनिवार, रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक स्कूली बच्चों समेत आम लोगों के अवलोकनार्थ (शारीरिक दूरी पालन करते हुए) खोलने का निर्णय सीएमपीडीआई प्रबंधन ने लिया है।

इस संग्रहालय में पृथ्वी की उत्पत्ति, मानव के विकास, कोयले की संरचना इत्यादि को प्रदर्शित करने वाली मॉडलों का आकर्षक एवं अद्भूत संग्रह है। कोयला भंडारों की उपस्थिति सहित भारत के कोयला संसाधनों पर विस्तृत सूचनाएं इसमें उपलब्ध है। खनिजों, चट्टानों तथा कीमती पत्थरों के असाधारण नमूने हैं, जो काफी आकर्षक तथा शिक्षाप्रद हैं। साथ ही, इसमें कोयला खनन के विभिन्न प्रकार के परिष्करण तथा कोयला उपयोग की गतिविधियों को दर्शानेवाले मॉडल विद्यमान हैं। खनन तथा खान बचाव ऑपरेशन के लिए उपयोग में लाये गये पुराने उपकरणों के बिरले नमूने भी इस संग्रहालय में है।

सीएमपीडीआई का यह भूगर्भ संग्रहालय सामान्य तौर पर भूगर्भ-विज्ञान, कोयला खनन तथा अन्य संबंधित गतिविधियों के महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्रदान करता है। पूर्वी भारत में इस प्रकार का यह एकमात्र संग्रहालय है। लगभग तीन दशक पूर्व स्थापित होने के बाद विगत वर्षों के दौरान कई गणमान्य, विभिन्न संस्थानों के उच्चाधिकारियों तथा स्कूली बच्चों ने इस संग्रहालय का अवलोकन किया है तथा इसके सौंदर्य एवं शैक्षणिक मूल्यों की प्रशंसा की है।

2021 इतिहास की 7वीं और अफ्रीका की सबसे गर्म जनवरी

इस वर्ष जनवरी का औसत तापमान सदी के औसत तापमान से 0.8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा थो वहीं अफ्रीका में यह अब तक की सबसे गर्म जनवरी थी

जनवरी 2021 इतिहास की 7वीं सबसे गर्म जनवरी थी। यह जानकारी एनओएए के नेशनल सेंटर्स फॉर एनवायर्नमेंटल इनफार्मेशन द्वारा जारी रिपोर्ट में सामने आई है। आंकड़ों से पता चला है कि इस वर्ष जनवरी का औसत तापमान सदी के औसत तापमान से 0.8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। वहीं यदि अफ्रीका की बात करें तो उसके लिए जनवरी 2021, इतिहास की सबसे गर्म जनवरी थी, जबकि उत्तरी अमेरिका में यह दूसरी सबसे गर्म जनवरी थी। इससे पहले जनवरी 2006 में वहां सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि इस वर्ष की शुरुआत ला नीना के साथ हुई थी। इसके बावजूद तापमान में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई। अफ्रीका में जनवरी 2021 का औसत तापमान 1910 से 2010 के औसत से 1.67 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले 2010 में जनवरी का तापमान औसत से 1.62 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया था। जहां उत्तरी एशिया के ज्यादातर भागों में तापमान सामान्य से कम था वहीं दक्षिण एशिया में यह सामान्य से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है।

गौरतलब है कि जनवरी 2020 इतिहास में अब

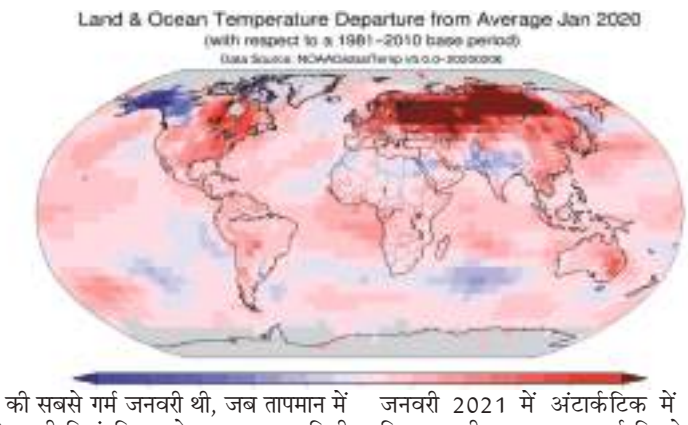

तक की सबसे गर्म जनवरी थी, जब तापमान में आने वाली विसंगति सबसे ज्यादा 1.15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई थी। इसके बाद जनवरी 2016 में 1.12 डिग्री सेल्सियस, 2017 में 0.98 डिग्री सेल्सियस, जनवरी 2019 में 0.94 डिग्री सेल्सियस, जनवरी 2007 में 0.92 डिग्री सेल्सियस, 2015 में 0.83 डिग्री सेल्सियस और जनवरी 2021 में 0.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। यदि आर्कटिक में जमी बर्फ की बात करें तो इस वर्ष जनवरी में उसका विस्तार 83.7 लाख वर्ग किलोमीटर आंका गया है, जोकि 1981 से 2010 के औसत से 6.5 फीसदी कम है। यह 43 वर्षों के इतिहास में छठी बार ऐसा हो रहा है जब जनवरी में इसका इतना कम विस्तार है। वहीं जनवरी 2021 में अंटार्कटिक में बर्फ का विस्तार करीब 29 लाख वर्ग किलोमीटर था, जोकि 1981 से 2010 के औसत से करीब 6.6 फीसदी कम है।

तापमान में हो रही इस वृद्धि से भारत भी अछूता नहीं है। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी रिपोर्ट से पता चला है कि 2020 भारतीय इतिहास का आठवां सबसे गर्म वर्ष था। इस वर्ष तापमान सामान्य से 0.29 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया था। गौरतलब है कि 2016 में अब तक का सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया था। जब तापमान 1980 से 2010 के औसत की तुलना में 0.71 डिग्री सेल्सियस अधिक था। यह स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि जलवायु में आ रहे बदलावों के चलते देश में तापमान लगातार बढ़ रहा है। यदि देश में तापमान के बढ़ने की रफ्तार को देखें तो अब तक के 12 सबसे गर्म साल हाल के पंद्रह वर्षों (2006 से 2020) के दौरान रिकॉर्ड किए गए थे।

क्या होंगे इसके परिणाम

हाल ही में यूएन द्वारा प्रकाशित "एमिशन गैप रिपोर्ट 2020" से पता चला है कि यदि तापमान में हो रही वृद्धि इसी तरह जारी रहती है, तो सदी के अंत तक यह वृद्धि 3.2 डिग्री सेल्सियस के पार चली जाएगी। जिसके विनाशकारी परिणाम झेलने होंगे। तापमान में आ रही इस वृद्धि का सीधा असर आम लोगों के जनजीवन पर पड़ेगा। जिस रफ्तार से तापमान में यह बढ़ोतरी हो रही है, उसके चलते बाढ़, सूखा, तूफान, हीट वेव, शीत लहर जैसी घटनाओं का आना आम बात होता जा रहा है। जिसका सबसे ज्यादा असर आम जन पर ही पड़ रहा है। कभी दशकों में पड़ने वाला विकराल सूखा आज हर साल पड़ रहा है। इसी तरह बाढ़ और तूफानों का आना भी आम होता जा रहा है। हम इन आपदाओं का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं, पर इसके असर को टाल नहीं सकते। डर है कि जिस तरह से तापमान में यह वृद्धि हो रही है, उसके कारण कहीं इंसानी महत्वाकांक्षा ही उसके विनाश का कारण तो नहीं बन जाएगी।

बढ़ता जा रहा टकराव

आज जैसे-जैसे इंसानी आबादी बढ़ रही है और जीवों के प्राकृतिक आवास सिकुड़ते जा रहे हैं, उसका असर इंसान और जानवरों के संबंधों पर भी पड़ रहा है। इस वजह से इंसानों और जानवरों के बीच आवास और भोजन के लिए टकराव भी बढ़ता जा रहा है। इस संघर्ष की कीमत इंसानों को अपनी फसल, मवेशियों और संपत्ति के रूप में चुकानी पड़ती है कभी-कभी इसका नतीजा उनकी मृत्यु का कारण भी बन रहा है। दूसरी तरह जानवर भी इस संघर्ष की भेंट चढ़ रहे हैं। कभी-कभी इसका शिकार वो जानवर भी बनते हैं जिनकी आबादी पहले ही खतरे में है ऐसे में उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। ऐसे में यदि इस संघर्ष एक कोई समाधान नहीं निकाला जाता तो इन जीवों के संरक्षण के लिए जो स्थानीय समर्थन प्राप्त होता है, वो भी कम होता जाता है। जिस पर ध्यान देने की जरुरत है।

जंगली जानवरों के साथ मनुष्यों का टकराव तो पाषाण काल से चला आ रहा है, पर हाल के दशकों में यह टकराव एकतरफा होते चला गया। मनुष्यों ने अपने स्वार्थ के लिये हाथियों से लेकर सभी वन्य जीवों के आवासों को बर्बाद कर दिया और अब वे अपने अस्तित्व को बचाने के लिये मनुष्यों से टकराव मोल ले रहे हैं? वन्य जीवों से टकराव में मनुष्यों की मौत दुखद है, पर यह भी एक सच है कि इसके कारण भी हम मनुष्य ही हैं।

पिछले 5 वर्षों में बाघ और हाथियों के हमले में मारे गए 2,729 लोग इनमें से 200 लोगों को बाघों के हमले में जबकि 2,529 को हाथियों के साथ हुए संघर्ष में अपनी जान गंवानी पड़ी थी 2016 से 2020 के बीच पिछले पांच वर्षों में बाघ और हाथियों के हमले में 2,729 लोग मारे गए थे। इनमें 200 लोग बाघों के हमले में जबकि 2,529 हाथियों के हमले में मारे गए थे। यह जानकारी 12 फरवरी 2020 को लोकसभा में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री बाबुल सुप्रियो द्वारा के प्रश्न के जवाब में सामने आई है। बाघों के हमले में मारे गए लोगों की बात करें तो पिछले पांच वर्षों में सबसे ज्यादा जानें महाराष्ट्र में गई हैं जहां इन सघर्षों के चलते 54 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इसके बाद उत्तरप्रदेश में 51, पश्चिम बंगाल में 44, मध्य प्रदेश में 23, राजस्थान में 7, उत्तराखंड में 6 और कर्नाटक में 5 लोगों की जान गई थी। यदि सिर्फ 2020 की बात करें तो सबसे ज्यादा जानें पश्चिम बंगाल में गई हैं जहां 5 लोग इन संघर्षों का शिकार बने थे। वहीं उत्तरप्रदेश में 4 लोगों की जान गई थी। कुल मिलाकर पिछले साल 13 लोग बाघों के हमले में मारे गए थे। अब ये तो पृथ्वी के सर्वशक्तिमान हम मनुष्यों को ही मंथन करना होगा कि आखिर इस टकराव को बगैर किसी की जान लिये कैसे रोका जा सकता है?

हिमाचल में कभी भी कहर ढा सकती हैं झीलें

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और अनुसंधान के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण राज्य परिषद और जलवायु परिवर्तन केंद्र की ओर से पिछले साल तीन रिवर बेसिन सतलुज, चिनाब और ब्यास को लेकर की गई स्टडी में चैंकाने और चेताने वाले आंकड़े सामने आ चुके हैं। जलवायु परिवर्तन केंद्र के आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के तीन रिवर बेसिन में 897 झीलें पाए गई हैं। इनके दायरे में वर्ष 2018 के मुकाबले में वृद्धि दर्ज की गई है। शोधकर्ताओं ने चिंता जाहिर की है कि यदि ग्लेशियरों के पिघलने का क्रम ऐसा ही जारी रहा तो इन झीलों के आकार में और वृद्धि होना तय है, जिससे भविष्य में भयानक बाढ़ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।

जलवायु परिवर्तन राज्य केंद्र द्वारा 2019 में किए गए शोध के आधार पर वर्ष 2019 में सतलुज बेसिन में 562 झीलों की उपस्थिति दर्ज की गई है, जिनमें से लगभग 81 प्रतिशत (458) झीलें 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल की है, 9 प्रतिशत (53) झीलें 5 से 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल और 9 प्रतिशत (51) झीलें 10 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की हैं। इसके अलावा चिनाब घाटी जिसमें चंद्रा, भागा और मियार सब बेसिन है, इनमें लगभग 242 झीलें हैं। चंद्रा में 52, भागा में 84 और मियार सब बेसिन में 139 झीलें हैं। वहीं, ब्यास घाटी जिसमें ऊपरी ब्यास, जीवा, पार्वती घाटियां सम्मिलत हैं, में 93 झीलें हैं। ऊपरी ब्यास में 12, जीवा में 41 और पार्वती सब बेसिन में 37 झीलें हैं। केंद्र द्वारा कहा गया है कि वर्ष 2018 की तुलना में 2019 में लगभग 43 प्रतिशत वृद्धि के संकेत दर्ज किए गए हैं। मौसम विभाग के डाटा के अनुसार जनवरी माह में पिछले 13 वर्षों में तीसरी बार शिमला और मनाली में बिल्कुल भी बर्फबारी नहीं देखी गई है। वहीं जनवरी माह में वर्षा के क्रम में 58 फीसदी और दिसंबर में 43.8 फीसदी की कमी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉ मनमोहन सिंह का कहना है कि पिछले कुछ सालों में बर्फबारी के ट्रेंड में थोडा बदलाव देखा गया है। जहां पहले ऊपरी क्षेत्रों में अक्टूबर माह में बर्फबारी देखी जाती थी वहीं अब यह दिसंबर में देखने को मिल रही है।

अपने उद्गम स्थल से ही संकट में है नर्मदा

निवेदिता खांडेकर

मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से ही नदी के अस्तित्व पर हमला शुरू हो गया है। नदी के उद्गम स्थल के अध्ययन में यह बात सामने आई है। उद्गम स्थल पर लोगों की बढ़ती आबादी, निर्माण और जंगल के ह्रास से नदी के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। घास के मैदानों का ह्रास और प्रदूषण की वजह से नदी दम तोड़ने लगी है।

अमरकंटक से नर्मदा के निकलते ही पहले तीन किलोमीटर में पांच चेक डैम और बैराज बनाए गए हैं जिससे नदी के कुदरती बहाव पर बुरा असर हुआ है। भारत सरकार और केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने नदी के विकास पर 50 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य नदी के प्राकृतिक स्वरूप को बचाने से अधिक उसके आसपास कंक्रीट का जंगल खड़ा करना है।

मध्य भारत की जीवन रेखा मानी जाने वाली नर्मदा नदी के लिए उद्गम स्थल से ही अस्तित्व का संकट शुरू होने लगा है। यह नदी मध्यप्रदेश के अमरकंटक के आस-पास के पहाड़ियों से निकलती है। इसके उद्गम में आस-पास के वनों की बड़ी भूमिका है। पर इन वनों का तेजी से ह्रास हो रहा है। इंसानी विकास से जुड़ी गतिविधियों से नदी का कुदरती बहाव भी खत्म हो रहा है। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन से नर्मदा पर मंडरा रहे इन खतरों की जानकारी सामने आई है। जर्नल ऑफ किंग साउद यूनिवर्सिटी के मार्च 2021 अंक में प्रकाशित इस अध्ययन में इन खतरों का विस्तृत वर्णन किया गया है।

पिछले चार दशक में नर्मदा नदी के कैचमेंट में जंगल कम हुए हैं। कृषि और दूसरी इंसानी जरूरतों के लिए पानी का दोहन बढ़ा है और इससे नदी की हालत खराब हुई है। अध्ययन का कहना है कि समृद्ध जैव-विविधता वाले इस क्षेत्र में 11.63 प्रतिशत डेंस मिक्स्ड फॉरेस्ट यानी सघन मिश्रित जंगल (डीएमएफ) है, वहीं 2.1 प्रतिशत हिस्सा साल के वृक्षों से भरा है। इस इलाके में वर्ष 1980 से 2018 तक में खुले हिस्से का 7.52 प्रतिशत विस्तार देखा गया है। खुले हिस्से के विस्तार से तात्पर्य वनों की कटाई से है। इंसानी आबादी वाले क्षेत्र या इमारतों वाले इलाके इस दौरान करीब 4.18 प्रतिशत बढ़ गए हैं। जमीन के प्रयोग में हुए बदलाव को समझने के मकसद से यह अध्ययन किया गया था। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का अमरकंटक शहर छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है। नर्मदा का उद्गम दो पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा और मैकल का मिलन स्थान भी है। पहाड़ियों की यह शृंखला कुछ इस कदर स्थित है कि वहां वर्षा जल की भारी मात्रा नदी में एकत्रित होती है। यहां से तीन नदियां तीन दिशाओं में निकलती हैं- नर्मदा, जोहिला और सोन।

नर्मदा के उद्गम स्थल का इलाका अमरकंटक पिछले चार दशक में अपनी हरियासली खो रहा है। नर्मदा के उद्गम स्थल का इलाका अमरकंटक पिछले चार दशक में अपनी हरियाली खो रहा है। अमरकंट में 1350 मिलीलीटर से 1600 मिलीलीटर तक औसत वर्षा होती है जो कि यहां के घने जंगल, समृद्ध जैव-विविधता, साल के पेड़ और असंख्य जड़ी-बूटि के पौधों के लिए वरदान की तरह है। उद्गम स्थल पर एक मंदिर है और यहीं एक पत्थर के तालाब का भी निर्माण हुआ है। यहीं से नर्मदा नदी निकलती है। रास्ते में कई वेटलैंड्स, तालाब, छोटी जल धाराएं मिलती जाती है और नर्मदा विशाल होती जाती है। इन जल धाराओं में कपिल, वैतरणी इत्यादि शामिल हैं। नर्मदा नदी उद्गम स्थल से ही कई खतरों को झेल रही है। वर्ष 1970 तक अमरकंट इंसानी विकास की विभीषिका से लगभग अछूता था। वर्ष 1960 में यहां बॉक्साइट का खनन शुरु हुआ था जिससे इस स्थान पर चहल-पहल बढ़ी। वर्ष 2000 में इस खदान को बंद कर दिया गया। वर्ष 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक शहर में मात्र 1,952 परिवार रहते है। यहां की कुल जनसंख्या 8,946 है। शहर में शांति का ऐसा आलम था कि कुछ 20 वर्ष पहले तक मात्र 35 से 40 दुकानें हुआ करती थी। वर्ष 2020 तक आते-आते उद्गम स्थल मंदिर के पास 100 दुकानें देखी जा सकती हैं, जिनमें से कुछ का पक्का निर्माण भी हुआ है। शहर में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या की वजह से यहां आश्रमों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। आश्रमों से निकलने वाला अपशिष्ट, नदी में बहाया जाता है। यहां के जंगल और जल-स्रोत प्रति वर्ष पांच लाख श्रद्धालुओं का भार झेल रहे हैं।

नर्मदा के लिए प्राण जितना महत्वपूर्ण जंगल हो रहा तबाह

इस अध्ययन में सामने आया है कि नर्मदा नदी को मजबूत करने वाली छोटी-छोटी जल धाराओं की धार कमजोर पड़ रही है। इसकी बड़ी वजह आसपास के जंगल का नष्ट होना है। इस अध्ययन के प्रमुख लेखक और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग के प्रमुख तरुण कुमार ठाकुर कहते हैं कि खुली जमीन और इंसानों द्वारा किये जा रहे निर्माण से नदी घाटी के लिए संकट उत्पन्न हो रहा है।''यहां जंगल समाप्त हो रहे हैं। अगर इसी तरह अवैज्ञानिकता के साथ इस इलाके की अवहेलना की जाती रही तो एक दिन सबकुछ खत्म हो जाएगा।अध्ययन में सामने आया है कि नर्मदा के उद्गम स्थल के आसपास रहने वाले लोगों द्वारा जंगल का दोहन भी किया जा रहा है जिसकी वजह से जंगल क्षीण हो रहे हैं।

उद्गम स्थल के मुख्य मंदिर के पुजारी धर्मेंद्र द्विवेदी कहते हैं कि पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक नर्मदा नदी को पांच जल धाराओं से पानी मिलता है। इसमें इंद्र दमन तालाब, बट्टे कृष्ण तालाब, सूरजकुंड और मार्कंडेय तालाब इत्यादि शामिल हैं। अमरकंटक से निकलने के बाद नर्मदा को कई निर्माणों को पार कर निकलना पड़ता है जिससे इसके प्राकृतिक बहाव पर असर होता है। अमरकंटक से निकलने के बाद नर्मदा को कई निर्माणों को पार कर निकलना पड़ता है जिससे इसके प्राकृतिक बहाव पर असर होता है। तस्वीर- अध्ययन से साभार कुछ वर्ष पहले प्रशासन ने दो जल धाराओं को जोड़कर मंदिर के आसपास ही घेरकर रख लिया था, जिससे वहां आए लोगों को नहाने के लिए पानी दिया जा सके। मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों के घरों से निकले कचरे (मल और गंदा पानी) को बिना सफाई किए ही नदी में जाने दिया जाता है। यहां जंगल का भी तेजी से समाप्त होना भी नर्मदा पर बढ़ रहे संकट की एक बड़ी वजह है। ''इस स्थान पर यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए जा रहे हैं।

तीन किलोमीटर में पांच अवरोध, कैसे बहेगी अविरल नर्मदा

उद्गम स्थल पर ही नर्मदा पर एक चेकडैम, अमरकंटक शहर में बने आश्रमों को पानी देने के लिए एक बांध सहित कई और रुकावट बनाए गए हैं। हालांकि, जंगल कम होने की वावजूद अच्छी बारिश और नदी के आसपास के इलाके की बनावट की वजह से नर्मदा में पानी की खास कमी नहीं हो रही है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अनूपपुर जिला पानी के मामले में सुरक्षित श्रेणी में आता है। बावजूद इसके आने वाले पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भूजल का खूब दोहन किया जा रहा है। जल आपूर्ति के लिए ही नदी की शुरुआत में ही कई चेक डैम बनाए गए हैं। पुष्कर सरोवर झील में जमी गाद को वर्ष 2020 में पहली बार निकाला गया। यहां आकर नर्मदा एक संकरी धारा के रूप में नजर आती है। इन अवरोधों की वजह से नदी का प्राकृतिक बहाव प्रभावित हुआ है। तस्वीर- निवेदिता खांडेकर

पुष्कर सरोवर झील में जमी गाद को वर्ष 2020 में पहली बार निकाला गया। यहां आकर नर्मदा एक संकरी धारा के रूप में नजर आती है। इन अवरोधों की वजह से नदी का प्राकृतिक बहाव प्रभावित हुआ है।

नदी कछार में निर्माण रोकने में असफल प्रशासन

वर्ष 2013 से लेकर 2017 तक राष्ट्रीय हरित अधिकरण या नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (एनजीटी) में नर्मदा में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर चार अलग-अलग आवेदन लगाए गए। मध्यप्रदेश सरकार ने एनजीटी को मार्च 2017 में कहा कि नर्मदा सेवा मिशन के तहत नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यावरण की चिंताओं के बावजूद सरकार का ध्यान इस स्थान के 'विकास' की तरफ है। यह विकास पर्यावरण का विनाश कर ही संभव है। हालांकि, सरकार अपनी इस मंशा से इनकार करती रही है।

हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में पावर प्रोजेक्ट्स का विरोध तेज

एजेंसियां

उत्तराखंड की घटना के बाद हिमाचल के लाहौल स्पीति के लोग एकजुट हुए और प्रस्तावित 56 पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया

उत्तराखंड में कुदरत का तबाही का मंजर सामने आने के बाद हिमाचल के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में प्रस्तावित 56 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। 8 फरवरी को लाहौल स्पीति जिले के सबसे बड़े गांव गोशाल और तांदी के लोगों ने बैठक की और इस बैठक में लोगों ने सरकार को उत्तराखंड की घटना से सबक सीखकर चंद्रभागा नदी पर प्रस्तावित पावर प्रोजेक्टों को रद्द करने की मांग की।

छह माह तक बर्फ की चपेट में घिरे रहने और प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से अति संवेदनशील यह जिला सिस्मिक जोन 4 में आता है। वहीं जिले में स्वास्थ्य सुविधांओं की कमी के चलते इस जिले में प्राकृतिक आपदांए आने पर भयंकर जान माल का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए जिले के लोगों ने बिजली की परियोजनाओं के खिलाफ पूरे जिले में जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। साथ ही गोशाल और तांदी गांव के लोगों ने पावर प्रोजेक्ट के लिए एनओसी न देने को लेकर पंचायत से प्रस्ताव भी पारित कर दिया है। लाहौल स्पीति जिले में प्रस्तावित हाइड्रो पावर प्रोजेक्टों का विरोध कर रही सेव लाहौल-स्पीति सोसायटी पूरे लाहौल स्पीति जिला में प्रोजेक्टों से होने वाले नुकसान के प्रति घाटी के लोगों को जागरूक कर रही है।

सोसायटी के उपाध्यक्ष विक्रम कटोच ने कहा कि अलकनंदा में जो हुआ उससे हम बहुत आहत हैं। इसलिए हम अपने जिले में इस तरह की घटना न घटे इसके लिए पहले से ही तैयारियों में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति जिला प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से अति संवेदनशील है। इसलिए जब यहां पर बड़े-बड़े पावर प्रोजेक्ट और बांध बनेंगे तो इसका यहां के पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर विपरित असर पड़ेगा। जिसका खामियाजा यहां के लोगों को उठाना पड़ेगा। वे लोग वर्ष 2005 से जिले में पावर प्रोजेक्टों के खिलाफ आंदोलनरत हैं और भविष्य में ये प्रोजेक्ट न बनें, इसके लिए हम हरेक गांव के लोगों को इस अभियान में जोड़ेंगे। इन पावर प्रोजेक्ट को रद्द करने को लेकर सोसायटी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा गया है।

गौशाल पंचायत की प्रधान सुशीला राणा ने कहा कि किसी भी सूरत में एसजेवीएनएल द्वारा बनाई जा रही 104 मेगावाट की तांदी परियोजना को अनापत्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। लाहौल स्पीति के लोग खेती पर निर्भर हैं और इन पावर प्रोजेक्ट से हमारी खेती की जमीन जलमग्न हो जाएगी। जिससे लोगों को रोजी-रोटी के लिए घाटी से बाहर पलायन करना पड़ेगा। तांदी पंचायत के उपप्रधान विरेंद्र कुमार का कहना है कि हम जिले में बन रहे प्रावर प्रोजेक्ट को विरोध कर रहे हैं और इनके निर्माण के लिए पंचायतों की ओर से किसी प्रकार का अनापति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

महिला मंडल गौशाल के सदस्य देकिड का कहना है कि लाहौल के लोग पर्यावरण के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। इसलिए हम अपने वनों में पूजा के लिए धूप तक ले जाने तक की रोक लगा रखी है। जिसकी वजह से वनों में आग की घटनांए नहीं होती है। ऐसे में हम अपने पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर बुरे असर डालने वाले इन भारी पावर प्रोजेक्टों को किसी भी सूरत मे शुरू नहीं होने देंगे। ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ के उप प्रधान बुधी चंद का कहना है कि हमारी और शकोली पंचायत के अधिन 12 बड़े गांव आते हैं और सर्दियों में भारी बर्फबारी के बाद इन इलाकों में हिमखंड गिरने का डर बना रहता है। इसलिए 126 मेगावाट का बरदंग प्रोजेक्ट के बनने से क्षेत्र में बुरा असर पड़ेगा। इनसे करीब एक दर्जन पंचायतों के हजारों लोग प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि चिनाब बेसिन में मौजूद पहाड़ और चट्टानें काफी कमजोर हैं। विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के समय होने वाली ब्लास्टिंग तथा अन्य कार्य पर्यावरण के लिए काफी घातक साबित होंगे। क्षेत्र की हरित पट्टी के जलमग्न होने के साथ-साथ यहां परंपरागत जलस्त्रोत भी खत्म हो जाएंगे। सैकड़ों हेक्टेयर भूमि पर फैले चरागाह तबाह हो जाएंगे। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं और इसके लिए हमने राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा है।

इन पावर प्रोजेक्ट की सरकार ने दी है अनुमति

सरकार ने चिनाब नदी से 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की योजना बनाई है। लंबे समय से प्रस्तावित पावर प्रोजेक्टों को लेकर हाल ही में हिमाचल सरकार ने सतलुज जल विद्युत निगम (एसजेवीएन), नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी), हिंदुस्तान पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की नामी बिजली कंपनियों को लगभग 1600 मेगावाट क्षमता के आधा दर्जन से अधिक के प्रोजेक्ट आवंटित किए हैं। इनमें 104 मेगावाट के तांदी, 130 मेगावाट के राशिल और 126 मेगावाट के बरदंग विद्युत प्रोजेक्ट एसजेवीएन को आवंटित किया गया है। 400 मेगावाट का शैली और 120 का मयाड़ प्रोजेक्ट एनटीपीसी, 300 मेगावाट का जिस्पा प्रोजेक्ट एचपीसीएल को आवंटित किया है।

धूम्रपान से हर साल वायुमंडल में मिलते हैं13.5 करोड़ किलोग्राम प्रदूषित कण

अध्ययन से अब यह पुष्टि हुई है कि पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) का एक छोटा भाग तंबाकू के धुएं से आता है, इसलिए हवा तंबाकू के धुएं से भी प्रदूषित होती है। माल्टा विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग के डॉ. नोएल एक्विलीना और प्रोफेसर इमैनुएल सिनाग्रा के द्वारा एक अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन इस बात की पुष्टि करता है कि कई जहरीले घटकों के अलावा एयरबोर्न पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) या कण प्रदूषण भी तंबाकू के धुएं से भी प्रदूषित होते हैं।

इस अध्ययन ने शोधकर्ताओं के 30 वर्षों के इंतजार को खत्म किया। 2016 में दुनिया भर में लगभग 6 ट्रिलियन सिगरेटों का उपयोग किया गया था। दुनिया भर में जाने-अंजाने दूसरों द्वारा किया जाने वाला धूम्रपान (सेकेंड हैंड स्मोक (एसएचएस)) अकेले सिगरेट पीने से, लगभग 2.2 करोड़ किलोग्राम निकोटीन और लगभग 13.5 करोड़ किलोग्राम पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) हर साल वायुमंडल में मिलता है। सेकेंड हैंड स्मोक (एसएचएस) पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) के उपयोग का पर्यावरणीय परिस्थितियों के तहत और कम सांद्रता में इसका पता लगाया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए, ऐतिहासिक रूप से कई अध्ययनों ने परिवेशी सेकेंड हैंड स्मोक के हवा तक पहुंच को दिखाने के लिए एक सबूत (मार्कर) खोजने की कोशिश की। जो 1991 से मुख्य सबूत के रूप में निकोटीन था।

भारत के 34.6 फीसदी ग्रामीण घरों तक पहुंच चुका है नल जल

भारत के 19.2 करोड़ ग्रामीण घरों में से 6.6 करोड़ घरों तक नल के जरिए पीने के पानी की आपूर्ति की जा रही है। जिसका मतलब है कि देश के 34.6 फीसदी ग्रामीण घरों तक नल के जरिए जल पहुंच चुका है। यह जानकारी जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा लोकसभा में दिए एक प्रश्न के जवाब में सामने आई है। जोकि जल जीवन मिशन (ग्रामीण) के आंकड़ों पर आधारित है। यदि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 100 फीसदी नल जल के लक्ष्य की बात करें तो आज देश के 2 राज्यों, 52 जिलों, 663 ब्लॉक, 40,086 पंचायतों और 76,196 गांवों तक नल के जरिए पीने का साफ़ जल पहुंच चुका है। देश में गोवा और तेलंगाना में हर ग्रामीण घर तक नल के जरिए पानी की व्यवस्था हो चुकी है। इनके बाद अंडमान निकोबार का नंबर आता है जहां के 88.2 फीसदी ग्रामीण घरों तक पानी पहुंचाया जा रहा है।

खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा है मिट्टी की घटती गुणवत्ता

एजेंसियां

2050 तक हमें 60 फीसदी ज्यादा अनाज पैदा करने की जरूरत होगी, जबकि दुनिया की आधी आबादी सूखे जैसे स्थितियों का सामना कर सकती है

मिट्टी आर्थिक और सामाजिक विकास में केंद्रीय भूमिका निभाती है। यह इंसान, पशु और वानस्पतिक जीवन के बने रहने के लिए अनाज, चारा, रेशा और अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करती है। इसलिए, समय-समय पर इसकी देखभाल की जरूरत होती है। खेती लायक जमीन को बढ़ाना मुश्किल है, इसलिए मौजूदा कृषि क्षेत्र पर ही उत्पादन का दबाव है।

ज्यादा अनाज उगाने की हमारी कोशिश में मिट्टी का इस हद तक दुरुपयोग हुआ है कि अब यह हमारी सेहत को प्रभावित करने लगा है। मिट्टी की गुणवत्ता विभिन्न भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं का नतीजा है। बहुत ज्यादा खेती, अत्यधिक दोहन जैविक और अजैविक स्रोतों से सीमित क्षतिपूर्ति के कारण मिट्टी की गुणवत्ता क्षीण हुई है। मिट्टी की गुणवत्ता में लगातार गिरावट को अक्सर उपज की स्थिरता या कमी के एक कारण के रूप में देखा जाता है। 2016 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की ओर से बनाया गया राष्ट्रीय डेटाबेस दिखाता है कि 12.07 करोड़ हेक्टेयर जमीन या भारत की कुल सिंचित और असिंचित भूमि का 36.7 फीसदी जमीन विभिन्न तरह की डिग्रेडेशन (भूमि ह्रास) की शिकार है। इसमें से 8.3 करोड़ हेक्टेयर (68.4 फीसदी) जमीन पानी से होने वाले कटाव की वजह से कमजोर हो रही है, जो मिट्टी को कमजोर करने वाली वजहों में सबसे बड़ी है। पानी का कटाव मिट्टी में जैविक कार्बन के नुकसान, पोषण असंतुलन, मिट्टी के ठोस होने, मिट्टी की जैव-विविधता घटने और भारी तत्वों व कीटनाशकों की मिलावट के रूप में सामने आता है।

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी (एनएएएस) के अनुसार, हमारे देश में मिट्टी के नुकसान की सालाना दर 15.35 टन प्रति हेक्टेयर है, जो 53.7 से 84 लाख टन पोषक तत्वों का नुकसान करती है। मिट्टी के नुकसान का तत्काल पड़ने वाला दूसरा असर फसल उत्पादकता में गिरावट है। कटाव वाली मिट्टी से जलाशयों में गाद जमा होती है और जलाशय की क्षमता घटती है, जिसके सालाना 1 से 2 फीसदी होने का आकलन है। यह आगे इसके कमान क्षेत्रों में सिंचाई को प्रभावित करता है।

एनएएएस के मुताबिक, भारत में पानी से होने वाले मृदा अपरदन से वर्षा आधारित प्रमुख फसलों में सालाना 1.34 करोड़ टन कम उत्पादन होता है, जो 205.32 अरब रुपए का नुकसान करता है। कुल जमीन में से 8.8 लाख हेक्टेयर जमीन स्थायी तौर पर पानी में डूबी रहती है और वर्षा आधारित मिट्टी में लगभग 1.25 करोड़ हेक्टेयर हिस्सा खरीफ में होने वाले अस्थायी जलभराव से परती रह जाती है। जलभराव, जो खारापन पैदा करके मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है और इसके चलते भारत में सालाना 12 से 60 लाख टन अनाज का नुकसान होता है। इसके अलावा भारत में उपजाऊ मिट्टी का बड़ा हिस्सा गैर-कृषि कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने से भी प्रभावित हुआ है।

रसायनों से होने वाला नुकसान

रसायनों से मिट्टी की सेहत को होने वाले नुकसान का पैमाना खारापन (क्षारीयता), अम्लीयता, रसायनों के कारण मिट्टी में आने वाली विषाक्तता और पोषक व जैविक तत्वों में गिरावट और अन्य पोषण संबंधी मुद्दों पर आधारित है। खारेपन से प्रभावित 67.4 लाख हेक्टेयर मिट्टी में 37.9 लाख हेक्टेयर में सोडियम की उच्च मात्रा (9.5 से ज्यादा पीएच मान) और 30 लाख हेक्टेयर खारेपन से प्रभावित मिट्टी शामिल है। पीएच मान के आधार पर देश का एक बड़ा हिस्सा औसत रूप से क्षारीय है।

उत्तर भारत के कुछ हिस्सों जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर (अविभाजित), पश्चिमी उत्तराखंड और पूर्व भारत जैसे ओडिशा, झारखंड, पूर्वी उत्तर और पश्चिमी तट प्रायद्वीप उच्च या औसत रूप से अम्लीय हैं। लगभग 1.1 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य जमीन बहुत कम उत्पादकता के साथ अत्यधिक मृदा अम्लीयता (5.5 से कम पीएच मान) से प्रभावित है (अनुपात बहुत ज्यादा क्रमशः 27.7:6.1:1 और 31.4:8.0:1 है)। यहां तक कि खादों की खपत भारत के 42 फीसदी जिलों में ही केंद्रित है। देश के कुल 525 जिलों में से 292 जिलों में ही कुल खादों के 85 फीसदी हिस्से की खपत होती है।

फसलों के बीच खादों के इस्तेमाल में भारी अंतर है। आलू, गन्ना, कपास, गेहूं और धान में क्रमशः 347.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 239.3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 192.6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 176.7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 165.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खादों का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा है। यहां तक कि इन फसलों में नाइट्रोजन वाली खादों का इस्तेमाल सबसे अधिक है। यूरिया का अत्यधिक इस्तेमाल मिट्टी को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। 2014-15 में देश में कुल इस्तेमाल होने वाली 48.5 करोड़ टन खाद में यूरिया का हिस्सा 30.6 करोड़ टन था। कृषि की स्थायी संसदीय समिति की 54वीं रिपोर्ट (2017-18) कहती है कि देश में खादों के इस्तेमाल में असंतुलन के पीछे यूरिया के पक्ष में झुकी हुई सब्सिडी नीति और अन्य खादों की ऊंची कीमतें है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि देश में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैशियम, सल्फर, जिंक, बोरान, मॉलिब्डेनम, आयरन, मैग्नीज और तांबे के लिए पोषक तत्वों की कमी क्रमशः 89 फीसदी, 80 फीसदी, 50 फीसदी, 41 फीसदी, 49 फीसदी, 33 फीसदी, 13 फीसदी, 12 फीसदी, 5 फीसदी और 3 फीसदी है। रिपोर्ट में कहा गया कि देश में रासायनिक खादों के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल को तार्किक बनाने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है, ताकि उपजाऊपन बहाल किया जा सके।

उपलब्धिः सीएमपीडीआई ने सुरंग सर्वेक्षण कार्य में कदम बढ़ाया

रांची : इरकॉन (IRCON) के लिए उधमपुर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल लिंक (यूएसबीआरएल) के कटरा-बनिहाल सेक्शन में जायरोस्कोपिक सर्वेक्षण को सफलतापूर्वक निष्पादित करके सीएमपीडीआई ने सुरंग के सर्वेक्षण में सफलता प्राप्त की है। यह कोलमाइंस में पारंपरिक सर्वेक्षण से एक बदलाव है और सर्वेक्षण क्षेत्र में सीएमपीडीआई के लिए नए आयाम जोड़ता है। उक्त परियोजना के लिए सीएमपीडीआई ने अत्याधुनिक डीएमटी मेक जायरोमैट 3000 सर्वेक्षण उपकरण का इस्तेमाल किया। सुरंग निर्माण में योजना के अनुसार संरेखन (एलाइनमेंट) रखना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि सुरंग खंडों के विभिन्न छोर निर्दिष्ट स्थानों पर मिलें। यह काम थकाऊ है क्योंकि सुरंग जमीनी स्तर से नीचे खोदी गई है। डिजाइन के अनुसार सुरंग के संरेखण पर नियंत्रण रखने के लिए मेसर्स इरकॉन ने समान और अन्य परिष्कृत उपकरणों का उपयोग करके सर्वेक्षण क्षेत्र में सीएमपीडीआई के पिछले क्रेडेंशियल्स को देखते हुए जायरो सर्वेक्षण का काम सौंपा। सीएमपीडीआई ने 27-01-2021 से 02-02-2021 तक यूएसबीआरएल के कटरा-बनिहाल खंड में चार सुरंगों में 18 स्थानों पर गायरो एजीमुथ के निर्धारण के लिए जायरोस्कोपिक सर्वेक्षण को सफलतापूर्वक सम्पन्न किया है। भारत सरकार की ऐसी प्रतिष्ठित रेलवे परियोजना का हिस्सा बनने पर न केवल सीएमपीडीआई बल्कि होल्डिंग कम्पनी कोल इंडिया के लिए भी यह गौरव का क्षण है और संस्थान की तकनीकी उत्कृष्टता का एक उदाहरण है।

वसंत पंचमी एक एतिहासिक दिन

वसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कण-कण खिल उठता है। मानव तो क्या पशु-पक्षी तक उल्लास से भर जाते हैं। हर दिन नयी उमंग से सूर्योदय होता है और नयी चेतना प्रदान कर अगले दिन फिर आने का आश्वासन देकर चला जाता है। यों तो माघ का यह पूरा मास ही उत्साह देने वाला है, पर वसंत पंचमी (माघ शुक्ल 5) का पर्व भारतीय जनजीवन को अनेक तरह से प्रभावित करता है। प्राचीनकाल से इसे ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती का जन्मदिवस माना जाता है। जो शिक्षाविद भारत और भारतीयता से प्रेम करते हैं, वे इस दिन मां शारदे की पूजा कर उनसे और अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। कलाकारों का तो कहना ही क्या? जो महत्व सैनिकों के लिए अपने शस्त्रों और विजयादशमी का है, जो विद्वानों के लिए अपनी पुस्तकों और व्यास पूर्णिमा का है, जो व्यापारियों के लिए अपने तराजू, बाट, बहीखातों और दीपावली का है, वही महत्व कलाकारों के लिए वसंत पंचमी का है। चाहे वे कवि हों या लेखक, गायक हों या वादक, नाटककार हों या नृत्यकार, सब दिन का प्रारम्भ अपने उपकरणों की पूजा और मां सरस्वती की वंदना से करते हैं।

यह हमें त्रेता युग से जोड़ती है। रावण द्वारा सीता के हरण के बाद श्रीराम उसकी खोज में दक्षिण की ओर बढ़े। इसमें जिन स्थानों पर वे गये, उनमें दण्डकारण्य भी था। यहीं शबरी नामक भीलनी रहती थी। जब राम उसकी कुटिया में पधारे, तो वह सुध-बुध खो बैठी और चख-चखकर मीठे बेर राम जी को खिलाने लगी। प्रेम में पगे जूठे बेरों वाली इस घटना को रामकथा के सभी गायकों ने अपने-अपने ढंग से प्रस्तुत किया।दंडकारण्य का वह क्षेत्र वर्तमान में गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला है। ऐतिहासिक महत्व

कई बड़ी एतिहासिक घटनाओं का दिन भी है वसंत पंचमी

वसंत पंचमी का दिन हमें पृथ्वीराज चौहान की भी याद दिलाता है। उन्होंने विदेशी हमलावर मोहम्मद ग़ोरी को 16 बार पराजित किया और उदारता दिखाते हुए हर बार जीवित छोड़ दिया, पर जब सत्रहवीं बार वे पराजित हुए, तो मोहम्मद ग़ोरी ने उन्हें नहीं छोड़ा। वह उन्हें अपने साथ अफगानिस्तान ले गया और उनकी आंखें फोड़ दीं। इसके बाद की घटना तो जगप्रसिद्ध ही है। मोहम्मद ग़ोरी ने मृत्युदंड देने से पूर्व उनके शब्दभेदी बाण का कमाल देखना चाहा। पृथ्वीराज के साथी कवि चंदबरदाई के परामर्श पर ग़ोरी ने ऊंचे स्थान पर बैठकर तवे पर चोट मारकर संकेत किया। तभी चंदबरदाई ने पृथ्वीराज को संदेश दिया।

चार बांस चौबीस गज, अंगुल अष्ट प्रमाण।
ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान ॥

पृथ्वीराज चौहान ने इस बार भूल नहीं की। उन्होंने तवे पर हुई चोट और चंदबरदाई के संकेत से अनुमान लगाकर जो बाण मारा, वह मोहम्मद ग़ोरी के सीने में जा धंसा। इसके बाद चंदबरदाई और पृथ्वीराज ने भी एक दूसरे के पेट में छुरा भौंककर आत्मबलिदान दे दिया। (1192 ई) यह घटना भी वसंत पंचमी वाले दिन ही हुई थी।

सिखों के लिए में बसंत पंचमी के दिन का बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन सिखों के दसवें गुरु, गुरु गोबिन्द सिंह जी का विवाह हुआ था।

वसंत पंचमी का लाहौर निवासी वीर हकीकत से भी गहरा सम्बन्ध है। एक दिन जब मुल्ला जी किसी काम से विद्यालय छोड़कर चले गये, तो सब बच्चे खेलने लगे, पर वह पढ़ता रहा। जब अन्य बच्चों ने उसे छेड़ा, तो दुर्गा मां की सौगंध दी। मुस्लिम बालकों ने दुर्गा मां की हंसी उड़ाई। हकीकत ने कहा कि यदि में तुम्हारी बीबी फातिमा के बारे में कुछ कहूं, तो तुम्हें कैसा लगेगा?बस फिर क्या था, मुल्ला जी के आते ही उन शरारती छात्रों ने शिकायत कर दी कि इसने बीबी फातिमा को गाली दी है। फिर तो बात बढ़ते हुए काजी तक जा पहुंची। मुस्लिम शासन में वही निर्णय हुआ, जिसकी अपेक्षा थी। आदेश हो गया कि या तो हकीकत मुसलमान बन जाये, अन्यथा उसे मृत्युदंड दिया जायेगा। हकीकत ने यह स्वीकार नहीं किया। परिणामतः उसे तलवार के घाट उतारने का फरमान जारी हो गया।

कहते हैं उसके भोले मुख को देखकर जल्लाद के हाथ से तलवार गिर गयी। हकीकत ने तलवार उसके हाथ में दी और कहा कि जब मैं बच्चा होकर अपने धर्म का पालन कर रहा हूं, तो तुम बड़े होकर अपने धर्म से क्यों विमुख हो रहे हो? इस पर जल्लाद ने दिल मजबूत कर तलवार चला दी, पर उस वीर का शीश धरती पर नहीं गिरा। वह आकाशमार्ग से सीधा स्वर्ग चला गया। यह घटना वसंत पंचमी (23.2.1734) को ही हुई थी। पाकिस्तान यद्यपि मुस्लिम देश है, पर हकीकत के आकाशगामी शीश की याद में वहां वसन्त पंचमी पर पतंगें उड़ाई जाती है। हकीकत लाहौर का निवासी था। अतः पतंगबाजी का सर्वाधिक जोर लाहौर में रहता है।

वसंत पंचमी हमें गुरू रामसिंह कूका की भी याद दिलाती है। उनका जन्म 1816 ई. में वसंत पंचमी पर लुधियाना के भैणी ग्राम में हुआ था। कुछ समय वे महाराजा रणजीत सिंह की सेना में रहे, फिर घर आकर खेतीबाड़ी में लग गये, पर आध्यात्मिक प्रवृत्ति होने के कारण इनके प्रवचन सुनने लोग आने लगे। धीरे-धीरे इनके शिष्यों का एक अलग पंथ ही बन गया, जो कूका पंथ कहलाया। उन्होंने भी सर्वप्रथम अंग्रेजी शासन का बहिष्कार कर अपनी स्वतंत्र डाक और प्रशासन व्यवस्था चलायी थी। प्रतिवर्ष मकर संक्रांति पर भैणी गांव में मेला लगता था। 1872 में मेले में आते समय उनके एक शिष्य को मुसलमानों ने घेर लिया। उन्होंने उसे पीटा और गोवध कर उसके मुंह में गोमांस ठूंस दिया। यह सुनकर गुरू रामसिंह के शिष्य भड़क गये। उन्होंने उस गांव पर हमला बोल दिया, पर दूसरी ओर से अंग्रेज सेना आ गयी। अतः युद्ध का पासा पलट गया।इस संघर्ष में अनेक कूका वीर शहीद हुए और 68 पकड़ लिये गये। इनमें से 50 को 1872 को मलेरकोटला में तोप के सामने खड़ाकर उड़ा दिया गया। शेष 18 को फांसी दी गयी। गुरू रामसिंह को भी पकड़कर बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया गया। 14 साल तक वहां कठोर अत्याचार सहकर 1885 ई. में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया।

मनोरंजन सिंह

रेशम कीट पालन बेहतर आय का माध्यम

...पेज एक का शेष

बढ़ावा देने तथा बाजार प्रबंधन व किस्मों के बचाव की आवश्यकता जताई. कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति डॉ ओएन सिंह ने कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा, प्रक्षेत्र प्रदर्शन व छात्रों के शोध कार्य में सहभागिता एवं सहयोग देने की बात कही.

स्वागत भाषण डीन एग्रीकल्चर डॉ एमएस यादव ने किया. संचालन श्रीमती शशि सिंह व धन्यवाद ज्ञापन डॉ निभा बाड़ा दी. मौके पर विवि के डीन, डायरेक्टर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स सहित तसर अनुसंधान संस्थान, नगड़ी, रांची के संकाय सदस्य भी मौजूद थे।

कर्रा स्टेशन में फुट ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए गार्डर लॉन्चिंग

रांची : यात्रियों की सुविधा के लिए रांची रेल मंडल के कर्रा स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है जिसके लिए 27- 27 मीटर के तीन गार्डर लगाए गए। हाल ही में कर्रा स्टेशन पर नये स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण किया गया है, साथ ही लो लेवल प्लेटफार्म के स्थान पर हाई लेवल प्लेटफार्म का निर्माण किया गया है । यात्रियों को प्लेटफार्म संख्या एक से प्लेटफार्म संख्या दो एवं तीन पर जाने के लिए तथा प्लेटफार्म संख्या दो एवं तीन से प्लेटफार्म संख्या एक पर आने के लिए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है । फुट ओवरब्रिज के निर्माण होने से यात्रियों को एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने एवं आने में काफी सहूलियत होगी। इस फुट ओवर ब्रिज की लंबाई 27 मीटर तथा चौड़ाई 03 मीटर है।

गार्डर लॉन्चिंग के लिए03 घंटे का ब्लॉक लिया गया । 140 टन के दो क्रेन, अन्य मशीनें, 50 मजदूर एवं 30 रेलवे कर्मचारी द्वारा इस कार्य को पूरा किया गया। उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) राम प्रताप मीणा, वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (ट्रेक्शन) ए आर दास, कोचिंग डिपो अधिकारी राजीव राशिक, मंडल अभियंता (दक्षिण) दीपक कुमार एवं सहायक मंडल अभियंता (निर्माण) एस के शर्मा तथा अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में गार्डर लॉन्चिंग के कार्य को संपन्न किया गया।

राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या ने सीसीएल में बैठक की

सीसीएल द्वारा महिला कर्मियों की सुरक्षा हेतु लिए गये पहल सराहनीयःचंद्रमुखी देवी

रांची संवाददाता

सीसीएल मुख्यालय, रांची स्थित 'कन्वेंशन सेंटर' में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या श्रीमती चंद्रमुखी देवीकी अध्यक्षता में सीसीएल में महिलाओं की सुरक्षा एवं अन्य संबंधित विषयों पर इंटरनल कमिटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निदेशक (कार्मिक), सीसीएल श्री विनय रंजन सहित इंटरनल कमिटी के अध्यक्षा महाप्रबंधक (समाधान सेल/भर्ती) सुश्री रश्मि दयाल, महाप्रबंधक (विधी) श्री पार्थो भट्टाचार्यजी, महाप्रबंधक (पी. एण्ड आई.आर.) श्री उमेश सिंह, महाप्रबंधक (कोटरे बसंतपूर) श्री गिरिश राठौर, सीएमएस सीसीएल श्रीमीत मंजू मिश्रा, श्रीमती अर्चना सिन्हा, श्रीमती रेखा पाण्डेय, श्रीमती अनुराधा प्रियदर्शनीएवं अन्य उपस्थित थे।

मुख्य अतिथि चंद्रमुखी देवी ने बैठक को संबोधित करते हुये कहा कि कार्यस्थलों पर एक स्वस्थ्य वातावरण निर्माण करना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है जिससे सभी महिलाकर्मी निर्भिक रूप से अपने कार्यनिष्पादन कर सकें। उन्होंने सीसीएल द्वारा महिलाकर्मियों हेतु एक सुरक्षित वातावरण बनाने की दिशा में किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने सरकार द्वारा महिलाकर्मियों को उनकी समस्याओं के निवारण एवं सुरक्षा प्रदान करने हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न व्यवस्थाओं के प्रति जागरूक करने व उसके प्रचार-प्रसार हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा। निदेशक (कार्मिक) विनय रंजन ने कहा कि सीसीएल प्रबंधन महिला कर्मियों की सुरक्षा के प्रति सैदव संवेदनशील रहा है और इस दिशा में हर संभव पहल किये गये जिसे भविष्य में भी जारी रखा जाएगा। उन्होंने सदस्य महोदया को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा बैठक में दिये गये निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन किया जाएगा।

मसूरी और उसके आसपास के इलाकों पर मंडरा रहा है बड़े भूस्खलन का खतरा

एजेंसियां : शोध के अनुसार मसूरी के आसपास का 15 फीसदी हिस्सा भूस्खलन की दृष्टि से अतिसंवेदनशील है, जबकि 56 फीसदी हिस्से में बहुत बड़े स्तर पर भूस्खलन आने की आशंका है। हाल ही में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी (डब्लयूआईएचजी) के वैज्ञानिकों द्वारा किये शोध से पता चला है कि मसूरी और उसके आसपास का इलाका भूस्खलन को लेकर अतिसंवेदनशील है इस शोध में वैज्ञानिकों ने निचले हिमालयी क्षेत्र में मसूरी और उसके आसपास के 84 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र का अध्ययन किया है जिससे पता चला है कि इस क्षेत्र का 15 फीसदी हिस्सा भूस्खलन को लेकर अतिसंवेदनशील है।

उत्तराखंड में बसा मसूरी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जहां पहले भी भूस्खलन की कई घटनाएं हो चुकी हैं जिसके लिए वैज्ञानिक इस इलाके में अनियंत्रित तरीके से हो रहे विकास को जिम्मेदार मानते हैं। वैज्ञानिकों ने इस इलाके में बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के खतरों को देखते हुए मसूरी और उसके आसपास के इलाकों का मानचित्रण किया है, जिससे इस क्षेत्र में भूस्खलन के प्रति संवेदनशीलता को समझा जा सके। शोधकर्ताओं के अनुसार जो क्षेत्र भूस्खलन के प्रति अतिसंवेदनशील है उसका एक बड़ा हिस्सा भाटाघाट, जॉर्ज एवरेस्ट, केम्प्टी फॉल, खट्टापानी, लाइब्रेरी रोड, गलोगीधार और हाथीपांव जैसे बसावट वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आता है यह क्षेत्र 60 डिग्री से अधिक ढलान वाला है।

बीएयू में बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीबिज़नस मैनेजमेंट व वेटनरी पीजी छात्रों का परीक्षाफल हुआ जारी

बीएयू में सहायक नियंत्रक का वाक इन इंटरव्यू 25 फरवरी को

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के सहायक निदेशक प्रशासन के द्वारा सहायक नियंत्रक के पद पर संविदा आधार पर बहाली के लिए बुधवार को अधिसूचना जारी की गयी है. कुल आठ पदो में चार पद अनारक्षित (सामान्य), दो पद एसटी तथा एससी व बीसी के लिए एक - एक पद पर नियुक्ति होगी. 65 वर्ष से कम आयु वाले स्नातक एवं लेखा एवं वित्त में किसी संस्थान में दस वर्षो का अनुभव वांक्षित योग्यता होगी. पेंशन मामले को हस्तगत अनुभव वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायगी.राज्य सरकार, केंद्र सरकार, लोक उपक्रम एवं विश्वविद्यालय से सेवानिवृत कर्मचारी/ पदाधिकारी आवेदन दे सकेंगे. अभ्यर्थियों को बायोडाटा, दो पासपोर्ट साइज़ रंगीन फोटो तथा योग्यता, उम्र, अनुभव प्रमाण-पत्र की मूल प्रति एवं सभी अभिलेखों की स्व-प्रमाणित छायाप्रति के साथ वाक इन इंटरव्यू में शामिल होना होगा. 25 फरवरी को विवि के प्रबंध पर्षद कक्ष में वाक इन इंटरव्यू होगी. विवि द्वारा अलग से कोई भी इंटरव्यू लैटर जारी नहीं किया जायेगा

रांची :बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों/संकायों में अध्ययनरत 16 पीजी / पीएचडी छात्र -छात्राओं का परीक्षाफल जारी कर दी गयी है. कॉलेज ऑफ़ बायोटेक्नोलॉजी के एमएससी (बायोटेक्नोलॉजी) पाठ्यक्रम में अध्ययनरत 12 छात्राओं को डिग्री के लिए सफल घोषित किया गया है. इनमें तृषा कुमारी, ट्विंकल मिश्र, नूरिमा फातिमा, निशत अंजुम, प्रगति प्रज्ञा, शालिनी कुमारी, शीमा इकबाल, शाहीना परवीन, पूजा कुमारी, नेहा रानी, अनीता कुमारी व प्रीति कुमारी शामिल है. वेटनरी संकाय के पीजी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत दो छात्रों का परीक्षाफल जारी किया गया है. इनमें आशा लता मुर्मू को एमएससी (वेटनरी फिजियोलॉजी) तथा ज्ञान रंजन सिन्हा को (वेटनरी एंड एनिमल हसबेंनडरी एक्सटेंशन एजुकेशन) डिग्री के लिए सफल सफल घोषित किया गया है.

कृषि संकाय के अनुवांशिकी एवं पौधा प्रजनन विभाग के अंजनी कुमार को पीएचडी (एग्रीकल्चर) इन जीपीबी डिग्री के लिए सफल सफल घोषित किया गया. जबकि कृषि संकाय के एग्रीबिज़नस मैनेजमेंट सेंटर में अध्ययनरत एक छात्र प्रिंस सिमोन कुंकल को एमबीए इन एग्रीबिज़नस मैनेजमेंट डिग्री के लिए सफल सफल घोषित किया गया. सभी छात्रों का परीक्षाफल बीएयू के उपसचिव (शिक्षा)

डॉ. शैलेश चटोपाध्याय द्वारा जारी की गयी है. डॉ चटोपाध्याय ने जानकारी दी कि कोविड -19 की वजह से महा-विद्यालयों/संकायों द्वारा दिसंबर व जनवरी माह में वर्चुअल माध्यम से इंटरव्यू तथा ऑनलाइन परीक्षा में सफल होने के उपरांत ही विश्वविद्यालय स्तर से छात्रों का परीक्षाफल जारी किया गया है. कुलपति के निर्देश पर पीजी/पीएचडी पाठ्यक्रमों को नियमित करने के सभी संभव प्रयास किये जा रहे है।

बाढ़ से सात दशक में एक लाख से ज्यादा मौतें, उत्तराखंड की स्थिति सबसे ज्यादा खराब

एजेंसियां

बाढ़ आपदा के कारण सर्वाधिक मृतकों की संख्या गंगा के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में है

पर्यावरण की नाजुक जगहें यदा-कदा चेताती रहती हैं। उत्तराखंड में 7 फरवरी, 2021 को चमोली में बिना किसी सूचना के अचानक आई भयावह बाढ़ एक और चेतावनी है। इस त्रासदी ने कई जिंदगियों को मिनटों में खत्म कर दिया। अब तक मिली सूचना के मुताबिक मलबे से अब तक करीब 52 शव निकाले जा चुके हैं जबकि अन्य 154 की तलाश जारी है। बाढ़ इतनी भयावह है तो इसका इलाज क्यों नहीं? हिमालयी उत्तराखंड की छोटी से छोटी हलचल नीचे मैदानों तक भी आती ही रहती है। लेकिन यदि बीते वर्षों की बाढ़ के कारण खत्म होने वाली जिदंगियों का आकलन करें तो उत्तराखंड का नाम सबसे ऊपर है।

बीते सात दशकों (1953-2017) तक 107,487 लोगों ने बाढ़ के कारण जिंदगियां खो चुके हैं। यह जानकर हैरानी हो सकती है कि बाढ़ मृतकों की करीब एक चौथाई संख्या महज दस (2008-2019) वर्षों की है। करीब 25 हजार लोग 2008 से 2019 तक बाढ़ और वर्षा के दौरान घटने वाली आपदाओं की वजह से मारे गए। इनमें 23,297 मृतक सिर्फ 15 राज्यों से हैं। बाढ़ आपदा के कारण सर्वाधिक मृतकों की संख्या गंगा के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में है। वहीं, बाढ़ के भुक्तभोगियों में शीर्ष पर उत्तराखंड है इसके बाद उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार का नाम शामिल है। बाढ़ के भुक्तभोगियों में उत्तराखंड ही शीर्ष पर क्यों है? इस सवाल पर ''गंगा आह्वान'' से जुड़ी मलिका भनोट ने बताया कि बाढ़ की विभीषिका का एक बड़ा कारण गंगा में अवरोध है। नदी को रोका जाए तो वह विभीषक बन जाती है। इसके अलावा उत्तराखंड में विकास के कार्यक्रम भी बहुत हद तक बाढ़ की विभीषिका को बढ़ा रहे हैं। 2013 की त्रासदी के बावजूद कदम संभाल कर नहीं रखा जा रहा। चारधाम परियोजना के लिए सड़क चौड़ीकरण में हजारों की संख्या में पेड़ काटे गए। यह पेड़ ही मिट्टी को बांधे रखते हैं। नतीजा है कि आए दिन भूस्खलन होता है। मलबे की अनियंत्रित डंपिंग ने नदियों की व्यवस्था को बिगाड़ दिया है। इसी समय बादल फटने या कम समय में ज्यादा वर्षा का होना आग में घी का काम करता है। उत्तराखंड में इस हलचल का दुष्परिणाम गंगा के मैदानी भागों में भी पड़ता रहता है। हिमालय में फूंक-फूंक कर कदम रखा जाना चाहिए।

वहीं, केंद्रीय जल आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1953 से लेकर 2011 तक के बाढ़ के नुकसान का आकलन यह दर्शाता है कि जिंदगियों के नुकसान के आधार पर सर्वाधिक तबाही वाले वर्षों में 1977 सबसे ऊपर है। 1977 में 11,316 लोगों की मृत्यु बाढ़ की वजह से हुई थी। फिर 1978 में 3,396 लोगों की मृत्यु हुई। 1979 में 3,637 लोगों की मृत्यु बाढ़ में हुई। इसके करीब एक दशक बाद 1988 में बाढ़ ने 4,252 जिंदगियां खत्म कर दी। करीब दो दशक बाद 2007 में 3,389 लोगों की जिदंगी बाढ़ में नेस्तानाबूद हो गई। यह सर्वाधिक मौत वाले वर्षों के आंकड़ों की सूची यही खत्म नहीं होती। बेहद अल्पविराम के बाद 2013 में उत्तराखंड में भीषण बाढ़ आई। इस बाढ़ में सरकारी आंकड़े के मुताबिक 3,547 लोगों की मृत्यु हुई। यह बीते चार दशकों की सबसे भीषण बाढ़ में एक थी। मृत्यु के यह आंकड़े उन मासूम लोगों के हैं जो शासन की अनीतियों के शिकार हुए। यह डिस्कलेमर भी देना जरूरी है कि मृतकों की गिनती और बाढ़ के नुकसान का कोई आकलन केंद्र सरकार नहीं करती है। केंद्र सरकार का कहना है कि बाढ़ राज्यों का विषय हैं। इसलिए बाढ़ के नुकसान के आकलन की जिम्मेदारी भी राज्यों की है। यह राज्य भी टेढ़ी खीर हैं। जब केंद्रीकरण होता है तब शोर मचता है कि राज्यों की हिस्सेदारी खत्म हो रही है, जब मानवता के काम उनके जिम्मे हैं तो वे गेंद केंद्र के पाले में डाल देती हैं। केंद्र और राज्यों के बीच गेंदों की फेंका-फेंकी का यह काम अनवरत चलता रहता है। गेंदों को एक-दूसरे के पाले में फेंकते रहना अदालतों में राज्य और केंद्र की नुमाइंदगी करने वाले प्रतिनिधि वकीलों की यह एक खास रणनीति भी रही है।

1980 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (आरबीए) की सिफारिशों में नदी के डूब क्षेत्र के अतिक्रमण एक बड़ी चिंता का विषय था। यह चिंता कुछ पन्नों की सिफारिशों में बदल गई और फिर कभी चिंतन का विषय नहीं बनी। पर्यावरण और कानून के जानकार एमसी मेहता ने 1985 में गंगा और उससे जुड़े मामले पर पहली बार शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। डाउन टू अर्थ से बातचीत में एमसी मेहता बताते हैं कि 1985 और उसके बाद 1986-87 में गंगा बेसिन को लेकर बातचीत शुरु हुई थी, इसमें बाढ़ के डूब क्षेत्र और उसके अतिक्रमण को लेकर भी बहस-मुबाहिसे हुए। अदालतों से तो लड़ाई जीत ली है लेकिन जमीनी नतीजा आजतक हासिल नहीं हुआ। सरकारें बदलती रहीं और किसी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई।

फोटो न्यूज

कही नरक की घाटी ना बन जाए? पतरातू घाटी

रांची :आज पतरातू की घाटी पूरे विश्व मे प्रसिद्ध हो गई है देश विदेश के सैलानी इस घाटी का लुत्फ उठाने आते है यहाँ का मौसम सदैव ही खुशनुमा रहता है इसलिए लोग यहाँ ज्यादा आना पसंद करते है। राँची से लगभग 28 की दूरी जहा घाटी का मनोरम दृश्य के साथ पतरातु लेक साथ ही पर्यटकों के लिए एक रिसोर्ट का भी निर्माण किया गया है अब यहां फिल्म सिटी खुलने की भी बात चल रही है पर विकास के साथ आज स्थिति बदलती नजर आ रही है अब धीरे-धीरे यहां गंदगी का अंबार लगते जा रहा है सोचे अगर इसी ताय यहाँ गंदगी का अम्बर लगता रहा तो किया होगा इस घाटी को धीरे धीरे कचरे का अंबार एक विशाल रूप ले लेगा । सैलानी यहां घूमने आते हैं और कचरा इधर उधर फेंक कर चले जाते हैं इसके रख रखाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं ना इसे कोई साफ करने वाला है इस चीज पर हम सबको सोचने की जरूरत है और अपने प्रकृति और अपने पर्यटक स्थल को बचाने की जरूरत है। **सचिन दास गोस्वामी**

जलवायु परिवर्तन और मानव निर्मित सीमाओं से बढ़ा वन्यजीवों को खतरा

एजेंसियां : शोधकर्ताओं ने 32,000 किमी की सीमाओं की पहचान की, जिनमें बाड़ और दीवारें लगाई गई हैं, जो जानवरों की बड़ी संख्या को अधिक उपयुक्त वातावरण में जाने से रोकते हैं।नए शोध के अनुसार, राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई दीवारें और बाड़ लगभग 700 स्तनपायी प्रजातियों को जलवायु परिवर्तन के अनुसार ढलने, उपयुक्त वातावरण में जाने में मुश्किल पैदा कर सकती है।

यूके के डरहम विश्वविद्यालय की अगुवाई में किए गए इस अध्ययन का उद्देश्य यह देखने के लिए किया गया है कि मानव निर्मित बाधाएं जानवरों की आवाजाही को कैसे रोक सकती हैं। जानवर रहने तथा भोजन की खोज में सीमाओं से अलग-अलग देशों में जाते रहते हैं।शोधकर्ताओं ने 32,000 किमी की सीमाओं की पहचान की, जिनमें बाड़ और दीवारें लगाई गई हैं, जो जानवरों की बड़ी संख्या को अधिक उपयुक्त वातावरण में जाने से रोकते हैं। शोधकर्ताओं ने बताया कि इन बाधाओं में से, अमेरिका-मेक्सिको सीमा की दीवार, चीन और रूस के बीच की सीमा के साथ बाड़ और भारत-म्यांमार सीमा के साथ बनाई जा रही बाड़ सबसे अधिक हानिकारक हो सकती है। शोधकर्ताओं ने हिसाब लगाया कि केवल अमेरिका-मेक्सिको सीमा की दीवार जलवायु परिवर्तन से विस्थापित 122 स्तनपायी प्रजातियों की आवाजाही को बाधित करती है।

दुनिया भर में मानव निर्मित सीमाओं से रोके जाने वाले स्तनधारियों में तेंदुए, बाघ और गंभीर रूप से लुप्तप्राय में सायगा मृग, चीता और जगुआर आदि शामिल हैं। राजनीतिक सीमाओं के बारे में समझने के साथ-साथ शोधकर्ताओं ने देशों के भीतर प्रजातियों पर पड़ रहे जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभावों की भी तुलना की। शोधकर्ताओं ने पाया कि जो देश उत्सर्जन कम करते है उन देशों में जैव विविधता को सबसे अधिक हानि हुई है। अधिक उत्सर्जन जलवायु परिवर्तन को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि एक तिहाई

स्तनधारियों और पक्षियों को जलवायु परिवर्तन के कारण 2070 तक अन्य देशों में उपयुक्त निवास स्थान खोजने की जरुरत पड़ेगी। इसका सबसे अधिक असर अमेज़ॅन वर्षावन और उष्णकटिबंधीय एंडीज़ के बीच, हिमालय के आसपास और मध्य और पूर्वी अफ़्रीका के कुछ हिस्सों में होने की आशंका है। शोधकर्ता इस समस्या को कम करने के लिए सीमा-पार से संरक्षण की पहल और जानवरों के आवासों को बचाने का सुझाव दे रहे हैं। उन्होंने दुनिया भर के नेताओं से यह भी आग्रह किया है कि नवंबर 2021 में ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में ग्रीनहाउस गैसों में महत्वाकांक्षी कटौती कर जैव विविधता के खतरे को कम करने के लिए कहा।डरहम विश्वविद्यालय के बायोसाइंसेज विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख अध्ययनकर्ता स्टीफन विलिस ने कहा कि धरती पर रहने वाली सभी प्रजातियों पर बदलती जलवायु का प्रभाव पड़ता है तथा वे इसपर प्रतिक्रिया करते हैं। हमारे निष्कर्ष बताते हैं कि प्रजातियों के राष्ट्रीय सीमाओं के माध्यम से दूसरे देशों में जाना महत्वपूर्ण है, ताकि वे जलवायु परिवर्तन का सामना कर सकें। सीमाएं जो दीवारों और बाड़ से बनी होती हैं, किसी भी प्रजाति के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करती हैं, वे इन बाधओं को पार कर दूसरी जगह नहीं पहुंच सकते हैं।

अगर हम प्रकृति की रक्षा के बारे में गंभीर हैं, तो सीमा संरक्षण की पहल का विस्तार करना और प्रजातियों पर सीमा अवरोधों के प्रभावों को कम करना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि इस मुद्दे में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से निपटने के लिए कोई विकल्प नहीं है। यह अध्ययन नेशनल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। कुल मिलाकर शोधकर्ताओं ने 12,700 स्तनपायी और पक्षी प्रजातियों के अवाजाही पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को देखा गया, जिनके निवास स्थान बढ़ते वैश्विक तापमान से प्रभावित हो सकते हैं, जिससे उन्हें नए घर खोजने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। उन्होंने पाया कि कम सीओ2 उत्सर्जन करने वाले गरीब देशों में पक्षी और स्तनपायी प्रजातियों की अधिक हानि होने का अनुमान है, जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन से अधिक प्रभावित होंगे।

डरहम विश्वविद्यालय के बायोसाइंसेज विभाग के शोधकर्ता मार्क टिटले ने कहा जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक योगदान देने वालों और जो सबसे अधिक प्रभावित होंगे, उनके बीच की असमानताएं अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं। शोधकर्ताओं ने बताया कि हमारे मॉडल यह भी दिखाते हैं कि पेरिस समझौते के अनुरूप मजबूत और तत्काल उत्सर्जन में कमी, जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभावों को बहुत कम कर सकती है और गरीब देशों पर इस तरह के नुकसान के बोझ से राहत दिला सकती है।

कैंपा फंड के तहत आदिवासियों के लिए 43.7 मिलियन रोज़गार उत्पन्न हुए

राज्य सभा में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो के एक बयान के अनुसार, राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (राष्ट्रीय प्राधिकरण) द्वारा आदिवासियों के बीच 43.7 मिलियन मानव रोजगार उत्पन्न किया गया।) 30 राज्यों में इसमें से छत्तीसगढ़ का हिस्सा 23 प्रतिशत है, उसके बाद ओडिशा (15 प्रतिशत) है।

बाघ के निवास में आक्रामक लैंटाना पौधों का प्रसार

सरकार ने पूरे भारत में बाघों के आवासों में आक्रामक लैंटाना पौधों के प्रसार पर गंभीरता से ध्यान दिया है, जिसके परिणामस्वरूप जंगली जड़ी-बूटियों के कारण देशी पौधों की कमी हुई है, यह जानकारी राज्य सभा में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने दी है। उन्होंने आगे कहा कि देश में बाघों के व्यापक मूल्यांकन के दौरान बाघों की आक्रामक प्रजातियों का प्रत्येक चौथे वर्ष होने वाले मूल्यांकन के आधार पर खाका तैयार किया जा रहा है।

कोरोनावायरस: क्या जलवायु परिवर्तन से पैदा हुआ ,फैला?

एजेंसियां: किसी एक क्षेत्र विशेष में जलवायु परिवर्तन के चलते चमगादड़ों की प्रजातियों में होने वाली वृद्धि इस वायरस के मनुष्यों में फैलने की सम्भावना को और बढ़ा सकती है। जिस तरह से बदलती जलवायु प्रकृति के हर पहलु को प्रभावित कर रही है, ऐसे में क्या कोविड-19 महामारी के उभरने में जलवायु परिवर्तन की कोई भूमिका थी, यह एक बड़ा सवाल है। जिसका जवाब शायद काफी हद तक वैज्ञानिकों ने ढूंढ़ लिया है। हाल ही में साइंस ऑफ द टोटल एनवायरमेंट जर्नल में एक शोध प्रकाशित हुआ है जिसमें इस बात की सम्भावना व्यक्त की है कि सार्स कोव-1 और सार्स कोव-2 (कोविड-19) के उद्भव में जलवायु परिवर्तन का हाथ हो सकता है।

गौरतलब है कि यह अपनी तरह का पहला अध्ययन है जो इस बात की ओर इशारा करता है कि कोविड-19 की उत्पत्ति में जलवायु परिवर्तन की भूमिका हो सकती है। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया भर के चमगादड़ों में करीब 3,000 तरह के कोरोनावायरस हैं। जिसका मतलब है कि चमगादड़ की हर प्रजाति में करीब 2.7 तरह के कोरोनावायरस हैं। ऐसे में किसी एक क्षेत्र विशेष में जलवायु परिवर्तन के चलते चमगादड़ों की प्रजातियों में होने वाली वृद्धि इस वायरस के मनुष्यों में फैलने की सम्भावना को और बढ़ा सकती है।

हालांकि चमगादड़ों में पाए जाने वाले अधिकांश कोरोनावायरस इंसानों में नहीं फैल सकते लेकिन इनमें कई ऐसे कोरोनावायरस की उत्पत्ति हो सकती है जो इंसानों को संक्रमित कर सकते हैं। इनमें से मर्स, सार्स कोव-1 और सार्स कोव-2 (कोविड-19) पहले ही इंसानों में फैल चुके हैं।

65 वें रेलवे सप्ताह पुरस्कार 2020 में रांची रेल मंडल को पुरस्कार

रांची मण्डल ने मण्डल रेल प्रबन्धक नीरज अंबष्ठ के नेतृत्व में सफलता के कई नए आयाम गढ़े हैं । दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्यालय गार्डेनरिच कोलकाता में हुए एक भव्य समारोह में महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व रेलवे संजय कुमार महांति ने द पू रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में रांची रेल मण्डल को 65वें रेलवे सप्ताह 2020 में कई महत्वपूर्ण पुरस्कार प्रदान किए।

क्षेत्रीय स्तर के शील्ड में पंकच्युलिटी शील्ड , वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबन्धक सह मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री नीरज कुमार द्वारा , सुरक्षा शील्ड मण्डल सुरक्षा आयुक्त प्रशांत यादव द्वारा , सर्वश्रेष्ठ कोचिंग डिपो शील्ड वरिष्ठ मण्डल यांत्रिक अभियंता पंकज कुमार द्वारा , रांची स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाला स्टेशन का शील्ड मिला जिसे रांची मण्डल के वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक अवनीश द्वारा एवं आउट स्टैंडिंग रिकवरी शील्ड को टीका राम मीना मण्डल लेखा अधिकारी (समन्वय) रांची द्वारा ग्रहण किया गया। रनिंग रूम शील्ड भी रांची मण्डल को मिला, जो रेलवे बोर्ड द्वारा दिया गया है। इसे मण्डल विद्युत अभियंता (ओपी) दीपांजन सरकार ने ग्रहण किया । गार्ड तथा लोको पायलट के

विश्राम हेतु इसे बहुत ही सुंदर बनाया गया है ।

देवमैन कैथवार ट्रैक मैनटेनर- बानो को रेलवे के नेशनल अवार्ड हेतु चुना गया है। उन्होने दिनांक 29.08.2019 को कुरकुरा महबूयांग स्टेशनों के बीच कि मी 507/14-15 पर मानसून रात्री गश्त के दौरान इनहोने करीब 02.45 बजे देखा कि लगातार हो रहे बारिश के कारण पहाड़ से भूस्खलन होकर पटरी के बीचों बीच करीब एक फुट ऊंचाई तक मिट्टी का जमाव हो चुका था । यह देखकर उन्होने तुरंत सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करते हुए ट्रेन संख्या 07010 को रोका और इसकी सूचना अपने प्रभारी एसएसई/पीडबल्यूएवाई/बानो को दिया। इसके पश्चात प्रभारी द्वारा 04.20 बजे अपने कर्मचारियों के साथ अवरोध स्थल पर पहुँचकर सभी बाधाओं को दूर करते हुए 04.50 बजे आवागमन कि शुरुआत कि गई । इनके सतर्कता एवं स्फूर्ति के कारण एक बड़े हादसे को टाला गया। इनके त्वरित एवं विवेकपूर्ण कारवाई को देखते हुए इन्हें रेलमंत्री ने पुरस्कृत किया है।

इसके अलावा बहुत से अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को क्षेत्रीय स्तर का पुरस्कार मिला है । उनके नाम इस प्रकार हैं। ग्रुप अवार्ड: प्रशांत कुमार यादव +03, व्यक्तिगत अवार्ड: डॉ देवराज बनर्जी , आशीष कुमार पांडे , बुद्दि प्रकाश मीना, अशोक कुमार ,सुलेन्द्र महतो , राजीव हेला, अमल कुंडु , संतोष कुमार , उदय कुमार , रवि संजय लकड़ा, नम्रता कुमारी , मो युनूस , सुशील नाथ तिवारी, विनय कुमार मिश्रा, राम प्रकाश उपाध्याय , प्रभु गञ्झु , संजीव कुमार मोहंती ।

बहुत से पुरस्कृत अधिकारियों कर्मचारियों ने कोरोना प्रोटोकॉल के कारण , अपर मण्डल रेल प्रबन्धक (ओपी) एम एम पंडित व अपर मण्डल रेल प्रबन्धक (इन्फ्रा) सतीश कुमार की अध्यक्षता मण्डल रेल प्रबन्धक के सभाकक्ष से ही इस कार्यक्रम का विडियो कान्फ्रेंसिग के जरिये अवलोकन किया।

यमुना प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का स्वत: संज्ञान, एनजीटी से मांगी रिपोर्ट

एजेंसियां

यमुना प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से दिल्ली जल बोर्ड के विरुद्ध जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते की मोहलत दी थी। यमुना में अनियंत्रित अमोनिया और अन्य प्रदूषकों के मामले की सुनवाई भले ही अब तक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में चला हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की है। अब तक दो सुनवाई हो चुकी है।

19 जनवरी, 2020 को दूसरी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी की ओर से यमुना प्रदूषण मामले को देखने वाली गठित समिति से अपनी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे वाली पीठ ने एनजीटी की गठित समिति को मामले में पक्षकारों में शामिल भी किया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषित नदियों के उपचार संबंधी मुद्दों पर स्वत: संज्ञान लिया था।

19 जनवरी, 2020 को सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता और मामले में न्याय मित्र मीनाक्षी अरोड़ा ने पीठ को जानकारी दी कि 18 जनवरी, 2020 को पानी की गुणवत्ता बेहतर थी और अमोनिया का स्तर भी नियंत्रित था। यदि यमुना की यही स्थिति बनी रहती है तो यह बेहतर होगी। वहीं, उन्होंने यह जानकारी भी दि कि हरियाणा सरकार

ने यमुना में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) की गुणवत्ता में सुधार करने का आश्वासन दिया है।

वहीं, दिल्ली और हरियाणा के बीच पानी के बंटवारे व प्रदूषण के आरोप-प्रत्यारोप पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक हफ्ते के भीतर दिल्ली जल बोर्ड के आरोपों पर अपना हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इससे पहले 13 जनवरी, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर पहली सुनवाई की थी और प्रदूषित नदी हिस्सों व एसटीपी और सीईटीपी की स्थितियों पर प्राधिकरणों से रिपोर्ट तलब की थी।

यमुना पुनरुद्धार के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने वाले यमुना जिए अभियान के संयोजक मनोज मिश्रा ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के फैसले के करीब पांच बरस बीत चुके हैं लेकिन जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी, वह अब तक नहीं की जा सकी है। सफाई के नाम पर अब भी प्राधिकरणों के लड़ाई-झगड़े और आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। वहीं, 25 मार्च से 31 मई, 2020 तक लगे लॉकडाउन के चलते तमाम गतिविधियों पर लगी रोक से यमुना को भी राहत की सांस मिली थी। अप्रैल, 2020 में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की रिपोर्ट में बताया गया था कि यमुना का पानी पिछले साल अप्रैल महीने की तुलना में काफी हद तक साफ हुआ है। समिति ने दिल्ली से गुजरने वाली यमुना में नौ जगहों से नमूने उठाए थे। इन नौ में से चार जगहों पर पानी में बीओडी (बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड) में 18 से लेकर 33 फीसदी तक की कमी आई थी। जबकि, यमुना में गिरने वाले नालों का पानी भी पहले की तुलना में साफ हुआ था।

दिल्ली में प्रवेश करने से पहले यमुना नदी अपेक्षाकृत साफ-सुथरी है। लेकिन, यहां पर प्रवेश करने के साथ ही यमुना का पानी बेहद गंदा होने लगता है। यह प्रदूषण इस हद तक है कि नदी के कई हिस्सों में जलीय जीवन का बचे रहना भी संभव नहीं रह गया है। इसी के चलते कुछ लोग यमुना को मृत नदी की संज्ञा भी देने लगे हैं। वहीं, लॉकडाउन के बाद यमुना के कई स्थानों पर प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ने लगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्वत: संज्ञान लिया है।

ग्लेशियरों के पिघलने से बनी झीलों के खतरे के लिए ग्लोबल वार्मिंग है जिम्मेवार

एजेंसियां

अध्ययन में पेरू के एंडीज में पाल्कोकाचा झील के मामले की जांच की गई, जो 1.5 लाख लोगों के लिए विनाशकारी हो सकता है

जैसे ही धरती गर्म होती है, ग्लेशियर खिसकने लगते हैं जिसकी वजह से दुनिया की पर्वतीय जल प्रणालियों में बदलाव आ रहे हैं। पहली बार ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और वाशिंगटन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मानवजनित जलवायु परिवर्तन को दुनिया की सबसे बड़ी बाढ़ के खतरों में से एक ग्लेशियरों के पिघलने से बनी झीलों को माना है।

अध्ययन में पेरू के एंडीज में पाल्कोकाचा झील के मामले की जांच की गई, जिससे हुआराज शहर में रहने वाले लगभग 1.5 लाख निवासियों के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित नए अध्ययन ने सबूत दिए हैं जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को इन सब के लिए जिम्मेदार माना गया है। वैज्ञानिक, यूडब्ल्यू अंतरिक्ष विज्ञान के प्रोफेसर और सह-अध्ययनकर्ता जेरार्ड रो ने कहा वैज्ञानिक चुनौती यह थी कि जलवायु परिवर्तन और बदलते बाढ़ के खतरों के बीच की कड़ी को स्पष्ट और सहीं तरीके से इसका मूल्यांकन करना था।

2016 में अध्ययनकर्ता रो और उनके सहयोगियों ने एक ग्लेशियर के अपने स्थान से खिसक जाने को क्या मानवजनित

जलवायु परिवर्तन से जोड़ा जा सकता है यह निर्धारित करने के लिए एक तरीका विकसित किया। पर्वतीय ग्लेशियरों के अपने स्थान से हटने के कई परिणाम हैं, जिसमें खिसकने वाले ग्लेशियर द्वारा छोड़े गए स्थान का घाटी में बदल जाना शामिल है।

ग्लेशियरों के पिघलने से बनी झीलों (ग्लेशियल झीलों) के निर्माण के लिए इन घाटियों में वर्षा और पिघला हुआ पानी इकट्ठा होता है। हाल के शोध में पता चला है कि दुनिया भर में ऊंचाई वाले ग्लेशियल झीलों की संख्या और आकार में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। रो ने बताया कि अध्ययन मानवजनित जलवायु परिवर्तन और बाढ़ के खतरे में बदलती ग्लेशियरों के पिघलने से बनी झीलों (ग्लेशियल झील) के बीच संबंधों का आकलन करने वाला पहला अध्ययन है। हमारे अध्ययन में उपयोग की जाने वाली विधियों को निश्चित रूप से दुनिया भर में अन्य ग्लेशियरों पर लागू किया जा सकता है।

नए अध्ययन ने पहले पल्काराजू ग्लेशियर के आसपास औद्योगिक युग की शुरुआत के बाद से तापमान वृद्धि में मानव उत्सर्जन की भूमिका की गणना की। इस बात की जानकारी है कि 1880 के बाद से इस क्षेत्र का तापमान 1डिग्री सेल्सियस बढ़ने के लिए 95 फीसदी मानव गतिविधियां जिम्मेदार है। अध्ययनकर्ताओं ने तब इन बढ़े तापमानों और ग्लेशियर के लंबे समय तक खिसकने के बीच संबंध का आकलन करने के लिए यूडब्ल्यू तकनीक का उपयोग किया, जिससे पालकोचा झील का विस्तार हुआ है। परिणाम बताते हैं कि पल्काराजू ग्लेशियर के खिसकने के पीछे 99 फीसदी से अधिक कारण मानवजनित जलवायु परिवर्तन हैं।

ऑक्सफोर्ड के डॉक्टरेट, मुख्य-अध्ययनकर्ता रूपर्ट स्टुअर्ट स्मिथ ने ग्लेशियल झील के प्रकोप से बाढ़ के खतरे का आकलन करने के लिए दो तरीकों का इस्तेमाल किया, जिसमें एक हिमस्खलन, भूस्खलन या रॉकफॉल एक सूनामी जैसी लहर को उत्पन्न करती है जो झील के किनारों को पूरी तरह भर देता है, जिसके कारण पालकोचा झील की वजह से हुआराज शहर के सामने आने वाली बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। स्टुअर्ट-स्मिथ ने कहा कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के माध्यम से जलवायु पर मानवजनित प्रभाव तापमान के बढ़ने के लिए जिम्मेदार है जैसा कि इस क्षेत्र में देखा गया है। अध्ययन से पता चलता है कि बढ़ते तापमान की वजह से पल्काराजू ग्लेशियर खिसका है, जिसके कारण बाढ़ का खतरा बहुत बढ़ गया है।

यह अध्ययन जर्मन अदालतों में चल रहे एक मामले के लिए भी नए सबूत प्रदान करता है जिसमें हुआराज के एक किसान शाऊल लुशनो लिउए ने ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने की भूमिका को लेकर जर्मनी के सबसे बड़े बिजली उत्पादक आरडब्ल्यूई पर मुकदमा दायर किया है। मुक़दमें में वर्तमान और भविष्य के बाढ़ के खतरों में कमी के उपायों की प्रतिपूर्ति की मांग की गई है।

स्टुअर्ट स्मिथ ने कहा हमारे निष्कर्ष, उत्सर्जन और सुरक्षा उपायों को लागू करने की आवश्यकता के बीच एक सीधा संबंध स्थापित करते हैं, साथ ही भविष्य में बाढ़ से होने वाले किसी भी नुकसान से निपटने की बात करते हैं। यह पहली बार नहीं है जब हुआराज शहर को जलवायु परिवर्तन से खतरा हुआ है। 1941 में, एक झील और पहाड़ खिसकने के परिणामस्वरूप, पाल्कोकाचा झील से भयंकर बाढ़ ने कम से कम 1,800 लोगों की जान ले ली थी। अध्ययन में यह भी पाया गया कि यह बाढ़ मानवजनित जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है। यह जलवायु परिवर्तन के सबसे पहले पहचाने गए घातक प्रभावों में से एक है।

रो ने कहा दुनिया भर में, पहाड़ी ग्लेशियरों का खिसकना जलवायु परिवर्तन के सबसे स्पष्ट संकेतकों में से एक है। बाढ़ का खतरा कई पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों को है, लेकिन यह जोखिम विशेष रूप से हुआराज और साथ ही एंडीज और नेपाल, भारत और भूटान जैसे देशों में भी गंभीर है, जहां अधिकतर आबादी संभावित बाढ़ के पानी के रास्ते में रहते हैं।

E ZONE CARE

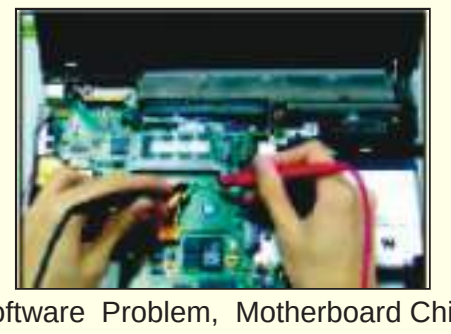

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

• **Repair your laptop with 3-month warranty.**

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, Ranchi 93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SUNDAY CLOSED

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मनोरंजन सिंह द्वारा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2,रातू रोड, रांची- 834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादक: एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : **JHAHIN/2019/78094**, email:greenrevolt2019@gmail.com. ☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।